

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी

वर्ष: 1

अंक: 13

कठुआ, शुनिवार 23 अगस्त 2025

पृष्ठ: 16

मूल्य: 5 रूपए

जम्मू-कश्मीर के शैक्षणिक संस्थानों को मानव पूंजी, नवाचार और अनुसंधान में निवेश करना चाहिए : एलजी

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को कहा कि मानव पूंजी, नवाचार और अनुसंधान में निवेश जम्मू-कश्मीर के शैक्षणिक संस्थानों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। सिन्हा गंदेरबल जिले में कश्मीर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के तुलमुल्ला परिसर में एक प्रशासनिक ब्लॉक और एक एम्प्लीट्यूडर का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे।

उपराज्यपाल ने शिक्षाविदों और छात्रों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान की आवश्यकता के बारे में बात की, और इस बात पर जोर दिया कि भारत अगले दो दशकों में विकसित भारत / 2047 के अंतिम उद्देश्य के साथ महत्वपूर्ण विकास के लिए तैयार है।



उन्होंने कहा, हमारे विकास मॉडल को मानव पूंजी के सृजन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। सिन्हा ने छात्रों के बीच आकर्षक शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराने, आलोचनात्मक सोच और जीवन

कौशल, समस्या समाधान और नवाचार को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमें सब चलता हैर वाले रवैये से छुटकारा पाना होगा और भारत को एक ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए कॉलेजों और विश्व

विद्यालयों के पुराने पाठ्यक्रमों में क्रांतिकारी बदलाव करने होंगे। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता मानव पूंजी, नवाच. र और अनुसंधान में निवेश होनी चाहिए। सिन्हा ने कहा कि अंतःविषयक पाठ्यक्रमों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि अंतःविषयक पाठ्यक्रम रचनात्मकता, नवाचार, सोच, कौशल विकसित करने के अलावा छात्रों को उनकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक बनाने में भी मदद करते हैं।

उपराज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय विकास की धुरी है और छात्र उसकी परिधि। मानव विकास कभी भी यांत्रिक नहीं होता। इसके लिए एक बेहतर विश्वविद्यालय,

■ शेष पेज 2...

कड़ी सुरक्षा और सीमित तीर्थयात्रियों के प्रवेश के बीच भद्रवाह में वार्षिक कैलाश यात्रा शुरू



सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू एवं कश्मीर के भद्रवाह में तीन दिवसीय वार्षिक कैलाश यात्रा बुधवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू हो गई।

स्थानीय देवता वासुकी नाग को समर्पित इस तीर्थयात्रा में कैलाश कुंड तक की यात्रा शामिल है, जो 14,241 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक झील है।

छड़ी मुबारक प्राचीन वासुकी नाग मंदिर से अनुष्ठानों, मंत्रोच्चार और धार्मिक उत्साह के साथ रवाना हुई। यात्रा भद्रवाह कस्बे से होकर गुजरी जहाँ जिला विकास समिति के अध्यक्ष धनंतर सिंह कोतवाल, विधायक दलीप सिंह परिहार, पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने तीर्थयात्रियों को गर्मजोशी से विदाई दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) संदीप मेहता ने कहा कि सभी ट्रैक और लंगर

■ शेष पेज 2...

विपक्ष के विरोध के बीच राज्यसभा ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पारित किया



सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : राज्यसभा ने गुरुवार को विपक्ष के विरोध और नारेबाजी के बीच ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक पारित कर दिया।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन विधेयक को राज्यसभा में विचार और पारित कराने के लिए पेश किया था। विधेयक के पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए, केंद्रीय मंत्री ने बताया कि विधेयक के तीन पहलू हैं - ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेमिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग, जिनमें से दो-तिहाई खंड (ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग) को बढ़ावा और प्रोत्साहन दिया जाएगा। राज्यसभा में बोलते हुए, वैष्णव ने कहा, ऑनलाइन गेमिंग एक महत्वपूर्ण विषय है जो डिजिटल दुनिया में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है।

■ शेष पेज 2...

मुख्यमंत्री ने वित्तीय, सामाजिक समावेशन योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को वित्तीय समावेशन योजनाओं, सामाजिक सुरक्षा कवरेज, जिला पूंजीगत व्यय और निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि (सीडीएफ) कार्यों की प्रगति की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने चालू वित्त वर्ष के लिए कर और गैर-कर राजस्व सहित जीएसटी संग्रह की भी समीक्षा की।

प्रधान सचिव (वित्त) संतोष डी. वैद्य ने वित्तीय एवं सामाजिक समावेशन योजनाओं, राजस्व सृजन प्रवृत्तियों तथा पूंजीगत व्यय एवं सीडीएफ कार्यों के अंतर्गत जिलावार प्रगति पर विस्तृत



प्रस्तुति दी।

मुख्यमंत्री ने कार्यों की अपलोडिंग और निविदा प्रक्रिया में धीमी गति पर ध्यान दिया।

अब्दुल्ला ने सभी विभागों और जिला प्रशासनों को राजस्व प्राप्ति और सामा. जिक समावेशन योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा सुधारात्मक उपायों को वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही तक

छोड़ने के बजाय मासिक आधार पर प्रगति की निगरानी करने का निर्देश दिया।

अब्दुल्ला ने कहा, विभागों को राजस्व लक्ष्यों को हासिल करने के लिए फरवरी या मार्च तक इंतजार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक विभाग को वित्त विभाग से विशिष्ट संदेश प्राप्त होगा

■ शेष पेज 2...

मानसून सत्र : लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, 14 विधेयक पेश, 12 पारित

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : गुरुवार को 18वीं लोकसभा का समापन हो गया जब अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। इसके साथ ही सत्र का अंत हो गया, जो कागजों पर विधायी उत्पादकता से चिह्नित था, लेकिन



बिहार की मतदाता सूची के विशेष

गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष के लगातार व्यवधान और मुखर विरोध से प्रभावित था। राज्य में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समापन कार्यवाही में भाग लेने के लिए दोपहर 12.04 बजे पहुंचे। अपने समापन भाषण में, अध्यक्ष

■ शेष पेज 2...

किश्तवाड़ बादल फटने की घटना : 33 लापता लोगों की तलाश के लिए बहु-एजेंसी तलाशी अभियान तेज

सबका जम्मू कश्मीर

चिसोटी (जम्मू-कश्मीर) : अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के बादल फटने से प्रभावित किश्तवाड़ जिले में 33 लापता लोगों की तलाश के लिए बहु-एजेंसी तलाशी अभियान गुरुवार को आठवें दिन में प्रवेश कर गया।

14 अगस्त को मचौल माता मंदिर के रास्ते में पड़ने वाले आखिरी गाँव में आई प्राकृतिक आपदा में मरने वालों की संख्या 65 हो गई है, जिनमें तीन सीआईएसएफ कर्मी और जम्मू-कश्मीर पुलिस का एक विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) शामिल हैं। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 33 लापता लोगों का पता लगाने के लिए कई एजेंसियों द्वारा तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। सबसे ज्यादा प्रभावित जगहों पर अलग-अलग टीमों अभियान चला रही हैं।

अभियान का केंद्र तीन जगहों पर हैकलंगर (साम. दायिक रसोई) के पास का मुख्य प्रभावित स्थान, वह इलाका जहाँ घर बह गए थे, और गुलाबगढ़-पद्मार इलाके में भुआट नाला।

■ शेष पेज 2...

जम्मू-कश्मीर के शैक्षणिक...

शिक्षक और बेहतर शिक्षण वातावरण की आवश्यकता होती है।

उन्होंने कहा, प्ोज विकास और विकसित होती तकनीक के कारण, हमें असाधारण गुणों वाले मानव संसाधनों की आवश्यकता है। उनमें आजीवन सीखने का कौशल और समय के साथ पुनः कौशल विकास और अप-स्किलिंग के लिए बदलाव की क्षमता होनी चाहिए।

कड़ी सुरक्षा और...

क्षेत्रों को सुरक्षित कर लिया गया है।

मेहता ने कहा, प्यात्रा भद्रवाह के वासुकिनाग मंदिर से शुरू हो गई है और हयान में रुकेगी। सभी रास्ते सुरक्षित कर लिए गए हैं। लंगर क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि ज़िला प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर दी है। उन्होंने कहा, ष्जुजुर्गों को यात्रा पर जाने से बचना चाहिए और सभी को यात्रा एडवाइजरी का पालन करना चाहिए।

अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में बादल फटने और खराब मौसम के कारण एहतियात के तौर पर इस वर्ष सीमित संख्या में तीर्थयात्रियों को ही अनुमति दी गई है।

कार्यक्रम के अनुसार, यात्रा 21 अगस्त को कैलाश कुंड पहुँचने से पहले हयान (नाल्थी) में रुकेगी, जहाँ श्रद्धालु पवित्र जल में डुबकी लगाएंगे। वापसी यात्रा 22 अगस्त को शुरू होगी।

उन्होंने बताया कि स्थानीय प्रशासन ने यात्रा के सुचारु संचालन के लिए मार्ग पर चिकित्सा दल तैनात किए हैं, पेयजल, बिजली, टेंट, जलाऊ लकड़ी और अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की हैं।

मुख्यमंत्री ने वित्तीय...

, जिसमें उनकी चिंता के क्षेत्रों को चिह्नित किया जाएगा और छह महीने के राजस्व लक्ष्य का विवरण दिया जाएगा। उन्हें एक स्पष्ट मासिक योजना के साथ, राजस्व प्राप्ति में सुधार के लिए आज से ही काम शुरू कर देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उपायुक्तों को वित्त विभाग से जिला-विशिष्ट निर्देश प्राप्त होंगे, विशेष रूप से सामाजिक कल्याण योजनाओं जैसे कि पीएम जन धन योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा योजना और विधवा, वृद्धावस्था और विकलांगता पेंशन के कवरेज के संबंध में।

अब्दुल्ला ने उपायुक्तों से प्रधानमंत्री जन धन योजना और अन्य योजनाओं के तहत खाताधारकों के नामांकन में गिरावट के कारणों का पता लगाने को कहा।

अब्दुल्ला ने कहा, ष्म तीन महीने बाद सामाजिक कल्याण योजनाओं की एक और समीक्षा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि जिला स्तर पर कवरेज में उल्लेखनीय सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने सीडीएफ के तहत कार्य योजनाओं को अंतिम रूप देने में तेजी लाने तथा कार्यों को बीईएएमएस पोर्टल पर अपलोड करने का आह्वान किया।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि विधायकों को यूटी और जिला कैपेक्स योजनाओं में शामिल कार्यों के बारे में सूचित किया जाए, जिन्हें विधायकों द्वारा पूर्व-बजट बैठकों के दौरान प्राथमिकता दी गई थी, और उन्हें अव्यवहारिक पाए गए कार्यों के बारे में सूचित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने आगाह किया कि राजस्व जुटाने में देरी से सरकार को विभागीय व्यय में कटौती जैसे कठिन निर्णय लेने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा, ष्थदि विभाग अपने व्यय में कटौती की स्थिति में नहीं आना चाहते, तो उन्हें राजस्व प्राप्ति में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। समय पर प्रगति सुनिश्चित करना प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारी है।

किश्तवाड़ बादल...

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस, सेना, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ), राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ), सीआईएसएफ, सीमा सड़क संगठन (बीआरओ), नागरिक प्रशासन और स्थानीय स्वयंसेवकों की संयुक्त टीमें इन जगहों पर बचाव कार्यों में लगी हुई हैं। अधिकारी ने बताया कि पिछले दो दिनों में दो शवों की बरामदगी के बाद, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस कर्मियों की एक टीम चिसोती से गुलाबगढ़ तक पूरे 22 किलोमीटर लंबे नाले में तलाशी अभियान चला रही है।

बचाव कार्यों में सहायता के लिए चिसोती में विशेष भारी ट्रक तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अधिकारी प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित निक।।सी सुनिश्चित करने और राहत प्रदान करने के लिए ऐसे वाहनों का उपयोग कर रहे हैं। एनडीआरएफ की 13वीं बटालियन के बचाव दल नदी-नालों के किनारे सक्रिय रूप से तलाशी अभियान चला रहे हैं और लापता लोगों का पता लगाने और उन्हें निकालने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं।

वे पूरी तरह से और सुरक्षित खोज सुनिश्चित करने के लिए बड़े-बड़े पत्थर और मलबा भी हटा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मलबे को छानने के लिए अर्थमूवर और खोजी कुत्तों सहित भारी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों की संख्या 65 है, लापता लोगों के कुछ अंग बरामद किए गए हैं और डीएनए पहचान प्रक्रिया शुरू हो गई है।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के निर्देश पर तैनात वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी जमीनी स्तर पर अभियान की निगरानी कर रहे हैं। बादल फटने से आई अचानक बाढ़ ने भारी तबाही मचाई, एक अस्थायी बाजार और वार्षिक मचौल माता यात्रा के लिए एक लंगर स्थल को तहस-नहस कर दिया सेना के इंजीनियरों ने रविवार को चिसोती नाले पर एक बेली ब्रिज का निर्माण किया, जिससे गाँव और मचौल माता मंदिर के बीच आवश्यक संपर्क बहाल हो गया।

सेना ने बचाव और राहत अभियान को तेज करने के प्रयासों के तहत कुछ ऑल-टेरेन वाहनों को भी शामिल किया है। बचावकर्मियों ने खोज में बाधा डाल रहे विशाल पत्थरों को उड़ाने के लिए आधा दर्जन से अधिक नियंत्रित विस्फोट भी किए। 25 जुलाई से शुरू होकर 5 सितंबर को समाप्त होने वाली वार्षिक मचौल माता यात्रा बुधवार को लगातार सातवें दिन स्थगित रही। हालांकि, अधिकारी जम्मू से छड़ी लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के एक समूह को अनुमति देंगे, जिनके 21 या 22 अगस्त को मंदिर पहुँचने की उम्मीद है। 9,500 फुट ऊँचे मंदिर तक 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा किश्तवाड़ शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर स्थित चिसोती से शुरू होती है।

मानसून सत्र....

ओम बिरला ने कुछ सदस्यों के आचरण पर गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसमें असंसदीय भाषा में लिखे तख्तियों और नारों के इस्तेमाल का हवाला दिया गया। इस बीच, सदस्य संसदीय मर्यादा का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए प्लोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहे। अध्यक्ष बिरला ने घोषणा की, उन्होंने सदन को सूचित किया कि, जैसा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सहमति हुई थी, चर्चा के लिए 120 घंटे आवंटित किए गए थे। हालांकि, विपक्षी सदस्यों द्वारा बार-बार और समन्वित व्यवधानों के कारण, केवल 37 घंटे का उपयोग किया गया था। अध्यक्ष बिड़ला ने कहा कि 419 तारांकित प्रश्न प्रस्तुत किए गए थे, फिर भी केवल 55 का ही उत्तर दिया गया। प्थह केवल एक प्रक्रियात्मक विफलता नहीं है। यह जनता के विश्वास का उल्लंघन है, उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि भारत के लोग जवाबदेही की उम्मीद करते हैं, नारे की नहीं। पूरे सत्र में 14 विधेयक पेश किए गए और 12 पारित हुए, जिनमें आयकर विधेयक, कराधान कानून (संशोधन) विधेयक और राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक शामिल हैं। ऑनलाइन गेमिंग विनियमन विधेयक। हालाँकि, संविधान विधेयक में 130वें संशोधन को संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था।

ऑनलाइन पहलगाम आतंकी हमले के प्रति भारत की रणनीतिक सैन्य प्रतिक्रिया – ऑपरेशन सिंदूर – पर 28–29 जुलाई को एक विशेष चर्चा हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने सदन को संबोधित किया। इस ऑपरेशन की सराहना एक सुनियोजित और दृढ़ आतंकवाद-रोधी पहल के रूप में की गई, जिसने भारत की रक्षा स्थिति को मजबूत किया।

सदन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा का भी समान रूप से जश्न मनाया गया, जिसने भारत की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर वापसी को चिह्नित किया। अध्यक्ष बिरला ने इस उपलब्धि की और प्रशंसा करते हुए इसे भारत की वैज्ञानिक उत्कृष्टता और वैश्विक नेतृत्व का प्रमाण कहा। इन प्रमुख बातों के बावजूद, कुछ सदस्यों के आचरण पर टिप्पणी करते हुए अध्यक्ष का स्वर कठोर हो गया।

उन्होंने कहा, नारे, तख्तियों और असंसदीय भाषा न केवल शिष्टाचार का उल्लंघन हैं, बल्कि लोकतांत्रिक भावना का अपमान भी हैं। हालाँकि, विपक्षी सदस्यों ने उनके समापन भाषण पर भी ध्यान नहीं दिया और प्लोट चोर गड्डी छोड़ जैसे नारे और भी जोर-शोर से लगाते रहे।

अध्यक्ष बिरला ने जोर देकर कहा कि सदन नाटकबाज़ी का मंच नहीं, बल्कि नीति और बहस का पवित्र स्थान है।

“हमारे आचरण पर पूरा देश नज़र रख रहा है। हमें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा,” उन्होंने कहा/ विपक्ष से व्यवस्था बहाल करने की उनकी अपील को नज़रअंदाज़ कर दिया गया और अंतिम क्षणों तक व्यवधान जारी रहा। इससे पहले, उन्होंने गुरुवार को प्राप्त कई स्थगन नोटिसों पर विचार करने से इनकार कर दिया, लेकिन कई समिति रिपोर्टों की प्रस्तुति सहित एक संक्षिप्त व्यवसाय की अनुमति दी; कल्याण वैजनाथराव काले ने रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट पेश की। गजेंद्र सिंह पटेल ने 2024–25 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की।

गृह मंत्रालय (नित्यानंद राय), पर्यावरण (कीर्तिवर्धन सिंह), बंदरगाह और जहाजरानी (शांतनु ठाकुर), सड़क परिवहन (अजय टट्टा), शिक्षा (सुकांत मजूमदार), और नागरिक उड्डयन (मुरलीधर मोहोल) सहित प्रमुख विभागों के मंत्रियों ने सदन के समक्ष विभागीय दस्तावेज रखे।

सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले, अध्यक्ष बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रचनात्मक रूप से भाग लेने वाले सभी सदस्यों का धन्यवाद किया और आगामी लोकसभा सत्रों में विचार-विमर्श, गरिमा और लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व के मूल्यों के प्रति पुनः प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया। 18वीं लोकसभा का मानसून सत्र समाप्त होने के साथ, अब देश बिहार विधानसभा चुनावों की ओर इस आशा के साथ देख रहा है कि अगला अध्याय संसदीय कार्यवाही की निष्पक्षता और प्रभावशीलता को पुनः स्थापित करेगा।

विपक्ष के विरोध...

इसके तीन खंड हैं – पहला खंड ई-स्पोर्ट्स है, जिसमें लोग टीम बनाकर खेलते हैं, समन्वय सीखते हैं, रणनीतिक सोच रखते हैं। हमारे खिलाड़ियों ने कई पदक भी जीते हैं। इस विधेयक में ई-स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा, इसके लिए एक प्राधिकरण बनाया जाएगा और इसे कानूनी मान्यता मिलेगी।

दूसरा है ऑनलाइन सोशल गेम्स जिसमें सॉलितेयर, शतरंज, सोडुकू आदि शामिल हैं। इस विधेयक में ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा दिया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा और एक प्राधिकरण बनाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि तीसरा खंड – शॉनलाइन मनी गेमस अब प्सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बन गया है। उन्होंने आगे कहा, शॉनलाइन गेमिंग की पूरी दुनिया में दो-तिहाई हिस्से को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन एक ऐसा ही तीसरा हिस्सा है – ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण समाज में, खासकर मध्यम वर्ग के युवाओं में एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है।

इसकी लत लग जाती है और परिवार की जमा-पूंजी खर्च हो जाती है। अनुमान है कि 45 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं और इसमें 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे गेमिंग डिसऑर्डर घोषित किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बन गया है। इससे मनोवैज्ञानिक विकार, बाध्यकारी व्यवहार, हिंसक व्यवहार जैसी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इसके कारण कई परिवार बर्बाद हो गए हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। इसका प्रमुख पहलू मनी लॉन्ड्रिंग है और इसका असर आतंकी गतिविधियों में भी देखा गया है। इस समस्या को रोकने के प्रयास हुए लेकिन यह समस्या बढ़ती ही गई। केंद्रीय मंत्री वैष्णव ने विधेयक को पारित करने के लिए सदन में पेश करते समय विपक्ष द्वारा हंगामा करने पर भी निशाना साधा।

उन्होंने कहा, ष्समय-समय पर समाज में अनेक अनियमितताएँ उत्पन्न होती हैं, ऐसे समय में सरकार और संसद की जिम्मेदारी है कि वे इन अनियमितताओं के विरुद्ध कार्रवाई करें और ऐसे समाधान निक.

‘डर को डराने वाले हैं, तेजस्वी आने वाले हैं,’ बिहार चुनाव के लिए आरजेडी ने जारी किया गाना

एजेंसी

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और राज्य के विभिन्न जिलों और इलाकों में जाकर बीजेपी और नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। यात्रा के दौरान वोट चोरी और चुनाव में धांधली का मुद्दा उठा रहे हैं। इस बीच, आरजेडी ने नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए नया नारा लॉन्च किया है। इस गाने में कहा गया है कि डर को डराने वाले तेजस्वी आने वाले हैं। आरजेडी के टवीटर पोस्ट में कहा गया है कि डर को डराने वाले हैं तेजस्वी आने वाले हैं. 20 साल की इस भ्रष्ट

सरकार ने बिहार और बिहारियों को सिर्फ “डर” दिया है. गाने में कहा गया है कि डर बेरा. `जगारी का, डर पलायन का, डर बाढ़ का, डर सपनों के टूटने का, डर बच्चों की पढ़ाई छूटने का, डर इलाज न करा पाने का, डर न्याय न मिलने का, डर घूसखोरों का, डर रिश्ततखोरा. ` का, डर अफसरशाही का, डर भ्रष्टाचार का! डर का डराने का चुनाव है इसमें कहा गया है कि बिहार की 14 करोड़ जनता इस बात की गवाह है. ये जो डर आज हर घर हर जीवन में इस सरकार ने पहुंचाया है, आने वाला चुनाव इस डर को डराने का चुनाव है, बिहार की धरती से इस डर को भगाने का चुनाव है. इसमें कहा गया है कि बिहार को तेजस्वी

जी के 17 महीनों वाल प्रगति और तरक्की वाला खुशहाल शासन चाहिए, हर हाल में चाहिए! इससे पहले तेजस्वी यादव ने वोट अधिकार यात्रा के दौरान नए संविधान संशोधन पर हमला बोला. तेजस्वी यादव ने केंद्र के नए विधेयक का मजाक उड़ाया, जो गंभीर आपरा. धिक आरोपों का सामना कर रहे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान करता है. उन्होंने इसे एनडीए के सहयोगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश बताया. तेजस्वी ने नीतीश और बीजेपी पर बोला हमला तेजस्वी ने कहा, `वे इसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए ला रहे हैं.

बिहार को मिली बड़ी सौगातरू राजेंद्र सेतु के विकल्प में नया पुल तैयार, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन

पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार में गंगा नदी पर बने 1.865 किमी लंबे छह लेन पुल का उद्घाटन करेंगे। यह पुल सात दशक पुराने राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। राजेंद्र सेतु की हालत जर्जर होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना पड़ता था। नया पुल बिहार के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।



एजेंसी

प्रधानमंत्री मोदी बिहार की जनता को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को छम्-31 पर 8.15 किलोमीटर लंबे औटा-सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिसमें पवित्र गंगा नदी पर 1.865 किमी लंबे 6 लेन वाला पुल भी शामिल है। इस परियोजना का बजट करीब 1,870 करोड़ रुपये है। यह पुल मोकामा और बेगूसराय को सीधा जोड़ेगा। इस पुल को सात दशक पुराने राजेंद्र सेतु के समानांतर बनाया गया है। पुराने पुल की हालत जर्जर होने की वजह से भारी वाहन यहां से नहीं निकल सकते और उन्हें दूरी तय करने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। नया पुल इस परेशानी को खत्म करेगा और ट्रैफिक जाम की भी समस्या कम होगी। बेहतर कनेक्टिविटी करेगा प्रदान पटना जिले के मोकामा और बेगूसराय के लोगों के लिए इस नये पुल का अलग ही महत्व

होगा। यह पुल उत्तर बिहार (बेगूसराय, सुपौल, मधुबनी और अररिया) और दक्षिण बिहार (पटना, शेखपुरा, नवादा और लखीसराय आदि) के बीच तेज और सीधा संपर्क साधने में मदद करेगा। साथ ही यह पुल प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सिमरिया धाम को भी बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह भारत का सबसे चौड़ा अतिरिक्त पुल होगा। इसका डिजाइन और निर्माण आधुनिक इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण माना जा रहा है।

आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा यह पुल बिहार के आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, खासकर उत्तर बिहार के लिए, जो कच्चे माल के लिए दक्षिण बिहार और झारखंड पर निर्भर है। साथ में यह पुल घरेलू उद्योगों और व्यापार को भी गति देगा। पुराने राजेंद्र सेतु की हालत खराब होने की वजह से किसानों और व्यापारियों को भारी वाहनों के जरिए अपने उत्पादों को बाजारों तक

पहुंचाने में मुश्किल होती थी, लेकिन इस नए पुल के निर्माण से यह काम आसान हो जाएगा। इसीलिए यह पुल सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि बिहार के आर्थिक विकास का माध्यम है।

बिहार के लोगों में दिखा उत्साह इस पुल के निर्माण को लेकर बिहार की जनता काफी उत्साह दिख रहा है। बेगूसराय निवासी राम कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आम आदमी की बड़ी सेवा कर रहे हैं। यह पुल पटना और बेगूसराय जिलों को करीब लाएगा, और लोगों को सुविधा प्रदान करेगा। उन्होंने कहा कि यह उन वाहनों के लिए यात्रा की दूरी को कम करेगा जो क्षतिग्रस्त पुल के कारण चक्कर लगाने के लिए मजबूर थे। वहीं मोनू राज कहते हैं कि बेगूसराय से पटना पहुंचने में 3 घंटे लगते थे, लेकिन अब हम 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि अब सिमरिया धाम में ज्यादा पर्यटक आएंगे। इसके साथ ही अन्य लोगों ने भी मोदी के द्वारा किए गए काम के प्रति अपना आभार जताया।

पुल बनाने के समय आई कई समस्याएं इस परियोजना के बारे में बात करते हुए छम्प अधिकारी एमएल योत्कर ने बताया कि इस परियोजना के निर्माण में हमारी टीम को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह एक निचला इलाका है, जहां हर साल बाढ़ का खतरा रहता है और इस बाढ़ की वजह से हर साल 7 से 8 महीने निर्माण ही कार्य संभव हो पाता है। बाढ़ की वजह से इन क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पुल से निर्माण से लोगों को काफी राहत मिलेगी।

मदरसा शिक्षकों को नीतीश ने ऐसे संभाला, मानदेय पर कर रहे थे हंगामा, खुद लिए आवेदन

बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह में सीएम नीतीश कुमार शामिल हुए। इस समारोह में मदरसा शिक्षकों ने सीएम की स्पीच पूरी होने के बाद जमकर हंगामा किया। दरअसल, मदरसा शिक्षकों से कहा गया था कि उनके मानदेय के लिए नीतीश कुमार बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन, सीएम ने कोई घोषणा नहीं की इसी के बाद पूरे सभागार में हंगामा शुरू हो गया।

एजेंसी

पटना में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। ज्ञान भवन में यह इवेंट हुआ। इसी आयोजन के दौरान प्रतिभागियों के एक ग्रुप ने सीएम नीतीश कुमार को कुछ कागजात देने की कोशिश की। इसका एक वीडियोभी सामने आया है, जिसमें लोग सीएम की तरफ कागज बढ़ाते दिख रहे हैं। उन्हें पुलिस रोकने की को. शिश कर रही है।

इस आयोजन में सीएम के सामने जमकर हंगामा हुआ। दरअसल, कार्यक्रम में सीएम के भाषण के बाद आक्रोशित शिक्षक पर्व लहराने लगे। मुस्लिम मदरसा शिक्षकों ने ग्रांट के लिए विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि 2011 में नीतीश कुमार ने वादा किया था 2459 प्लस मदरसों को तनखाह देंगे। उनमें से 1646 मदरसे बच गए हैं। कार्यक्रम में नारे लगाए गए।

शिक्षकों ने क्यों किया हंगामा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के बापू सभागार में अल्पसंख्यक संवाद बुलाया था। इस संवाद के लिए पूरे बिहार से बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुंचे थे। जगह कम पड़ गई। जितने लोग अंदर थे उससे ज्यादा बाहर थे। बड़ी संख्या में मदरसा शिक्षक पहुंचे थे, शिक्षकों से कहा गया था कि उनके मानदेय के लिए नीतीश कुमार बड़ा ऐलान करेंगे। लेकिन, सीएम की स्पीच में ऐसा कुछ नहीं था। जिसके बाद पूरे सभागार में हंगामा शुरू हो गया। नीतीश कुमार के सामने ही हंगामा शुरू हुआ, कागज लहराए जाने लगे भड़के लोग मंच के सामने पहुंच गए। नीतीश कुमार ने कुछ लोगों से उनके हाथ का कागज खुद लिया, लेकिन मदरसा शिक्षकों की नारा. जगी बढ़ती देख नीतीश कुमार को वहां से निकाला गया। 1646 ऐसे मदरसों के शिक्षक यहां पहुंचे थे जिन्हें सरकार से कोई मानदेय नहीं मिलता है। मदरसा शिक्षकों ने सभा में खूब नारेबाजी और हंगामा किया। शिक्षकों ने कहा, आज इन मदरसों को लेकर घोषणा

होनी थी और यही बोलकर बुलाया गया था। लेकिन, सीएम नीतीश ने अपने भाषण के दौरान कुछ भी बड़ी घोषणा नहीं की। सीएम ने गिनाई अपनी पार्टी की कामयाबी सीएम नीतीश कुमार ने इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए गिनाया कि उनकी सरकार ने मुसलमानों के लिए कितना काम किया है। सीएम ने कहा, पहले सरकार में कुछ नहीं था, हमारी सरकार बनने के बाद काम हुआ। पहले कितना बुरा हाल था। एनडीए की सरकार 2005 में बनी तब से काम हुआ। नई सरकार के गठन के बाद से मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया गया। पहले हिंदु-मुस्लिमों के बीच झगड़ा होता था। सीएम की स्पीच के बाद ही हंगामा हो गया और शिक्षकों ने कुछ कागजात दिखाते शुरू किए। हंगामे के बाद सीएम नीतीश कुमार ने मदरसा शिक्षकों से ज्ञापन लिया। बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड का गठन 1922 में हुआ था। फिर 1981 में अधिनियम बनने के बाद बोर्ड को स्वायत्त अधिकार मिले और राज्य के मदरसों को ग्रांट और मान्यता देने की प्रक्रिया मजबूत हुई।

उपराष्ट्रपति चुनाव में जब आखिरी बार उतरा था तमिलनाडु का उम्मीदवार, तब क्डझ ने किसको दिया था वोट?

एजेंसी

9 सितंबर को देश को अगला उपराष्ट्रपति मिल जाएगा। लड़ाई एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और इंडिया के बी सुदर्शन रेड्डी के बीच है। 19वें क्डझ समेत कई पार्टियों ने तमिलनाडु में दलों से कहा है कि वे अपने राज्य के नेता राधाकृष्णन के लिए वोट करें। ये चुनाव तमिलनाडु के लिए खास है, क्योंकि 41 साल बाद वहां का कोई उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के चुनाव में है। आखिरी बार तमिलनाडु से किसी उम्मीदवार को इस पद के लिए उतारा गया था तो वो थे आर. वेंकटरमन।

इस बार के चुनाव में कांग्रेस की सहयोगी और तमिलनाडु की सत्ता पर काबिज क्डझ ने अपने पते खोल दिए हैं। स्टालिन की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की बात कही है। संसद के दोनों सदनों में एनडीए के संख्याबल के कारण राधाकृष्णन की जीत पक्की मानी जा रही है, लेकिन डीएमके और उसके सहयोगी राजनीतिक कारणों से उनका विरोध करेंगे।

1984 के चुनाव में क्या था क्डझ का रुख? हालांकि, द्रविड़ पार्टी के लिए ऐसा रुख कोई नई बात नहीं है। 1 अगस्त 1984 को कांग्रेस (आई) संसदीय बोर्ड ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री रहे आर वेंकटरमन को उपराष्ट्रपति पद के लिए औपचारिक रूप से नामित किया। इससे पहले, उन्होंने मद्रास में विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में कार्य किया था और राज्य के औद्योग. िकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

डीएमके के मुखपत्र मुरासोली की रिपोर्टों का हवाला देते हुए द डीएमके इयर्स के लेखक आर कन्नन ने लिखा कि आम सहमति बनाने में विफल रहने पर विपक्षी दलों के नेता डीएमके के एरा मोहन, बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी और सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता शामिल ने 2 अगस्त 1984 को एक बैठक बुलाई और रिपब्लिकन पार्टी के पूर्व सांसद बी सी कांबले को अपने संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से पता था कि यह मुकाबला केवल औपचारिकता मात्र का होगा।

वेंकटरमन ने बड़े अंतर से दर्ज की जीत कहा गया कि विपक्ष का वेंकटरमन के प्रति कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, लेकिन उन्हें इस बात का अफसोस है कि प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय सहमति के आधार पर उम्मीदवार चुनने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया। विपक्ष चाहता था कि कमजोर वर्ग के किसी सदस्य को उपराष्ट्रपति पद का अवसर दिया जाए।

सार्क को फिर से शुरू करने और शांति कायम करने के लिए कदम उठाएं : फारूक अब्दुल्ला

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को पुनर्जीवित करने का आह्वान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने और भारत को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ाने में मदद करने का आग्रह किया है।

पत्रकार शाहिद सिद्दीकी के संस्मरण आई, वितनेस : इंडिया फ्रॉम नेहरू टू नरेंद्र मोदी के विमोचन के अवसर पर बुधवार को बोलते हुए अब्दुल्ला ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया मुलाकात का उदाहरण दिया, जिसके बाद ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, षमय आ गया है जब हमारे प्रधानमंत्री (मोदी) को भी ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे भारत शांति के लिए दुनिया के साथ चल सके... सार्क को फिर से शुरू करने का समय आ गया है।

हमें अपनी ओर से कड़े कदम उठाने होंगे और शांति का मार्ग खोजना होगा – पूरी दुनिया की शांति के लिए। दुनिया बहुत छोटी हो गई है, और अगर हम इस छोटी सी दुनिया को प्यार से नहीं रख सकते, तो यह दुनिया हमें छोड़ देगी। 1985 में स्थापित, सार्क एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन और दक्षिण एशियाई देशों का भू-राजनीतिक संघ है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान शामिल हैं। सार्क बैठकों से उभरे कई परियोजनाओं और पहलों के बावजूद, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने समय-समय पर क्षेत्रीय सहयोग और सार्क-संबंधी गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डाला है।

लघु उद्योग भारती ने सत शर्मा से की मुलाकात, औद्योगिक पैकेज बढ़ाने को कहा

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : लघु उद्योग भारती, जम्मू और कश्मीर के एक प्रतिनिधिमंडल ने अपने अध्यक्ष परवीन परगाल के नेतृत्व में वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गुप्ता, उपाध्यक्ष अंकित गुप्ता, महासचिव आगम जैन और वित्त सचिव और कोषाध्यक्ष इशांत गुप्ता के साथ आज जम्मू और कश्मीर भाजपा अध्यक्ष सत शर्मा (सीए) से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

इस अवसर पर सत शर्मा के साथ जम्मू-कश्मीर भाजपा महासचिव गोपाल महाजन और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। प्रतिनिधिमंडल ने इस बात पर जोर दिया कि नई केंद्रीय क्षेत्र योजना (एनसीएसएस) जम्मू-कश्मीर के निवेश माहौल को बदलने में एक ऐतिहासिक पहल रही है, खासकर अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्त होने के बाद। हालाँकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 को समाप्त हो गई है, जिससे सैकड़ों वास्तविक निवेशक और उद्यमी अनिश्चितता में हैं।

यदि इस योजना के तहत प्रोत्साहनों को बढ़ाया और सुरक्षित नहीं किया गया, तो इससे केंद्र शासित प्रदेश में औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निवेशकों के विश्वास पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

ज्ञापन में, लघु उद्योग भारती ने बताया कि यद्यपि केंद्र सरकार ने 2021 से 2037 तक, 16 वर्षों में वितरित किए जाने वाले 28,400 करोड़ रुपये के महत्वाकांक्षी निवेश पैकेज की घोषणा की थी, लेकिन क्षेत्र की व्यापक विकासात्मक आवश्यकताओं की तुलना में यह आवंटन और समयावधि अपर्याप्त साबित हुई है।

प्रतिनिधिमंडल ने आगे रेखांकित किया कि नीति कार्यान्वयन के तीन वर्षों के बावजूद, भूमि आवंटन में देरी, औद्योगिक सम्पदाओं के अपर्याप्त विकास और प्रोत्साहनों के असमान वितरण के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, जहाँ कुछ बड़े उद्योगों को लाभ का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त हुआ है जबकि छोटे निवेशक और एमएसएमई पीछे छूट गए हैं।

ज्ञापन में कहा गया है कि जुलाई और सितंबर 2024 के बीच शुरुआती निवेश करने वाले कई नए निवेशकों, स्टार्टअप्स और

एमएसएमई सहित एक हजार से ज्यादा आवेदन अभी भी लंबित हैं, जबकि भूमि अधिग्रहण, प्रदूषण नियंत्रण, बैंक ऋण स्वीकृति और व्यवहार्यता अध्ययन जैसी प्रक्रियाओं पर काफी समय और संसाधन खर्च हो चुके हैं। अगर उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया गया, तो उनकी मेहनत बेकार जाएगी।

लघु उद्योग भारती ने आग्रह किया कि समान वितरण सुनिश्चित करने और जम्मू-कश्मीर के लिए एक अधिक व्यापक विकास रणनीति को समर्थन देने हेतु कुल प्रोत्साहन आवंटन को बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपये किया जाए। इसने यह भी अनुरोध किया कि पंजीकरण की समय सीमा दो वर्ष बढ़ाकर 30 सितंबर 2026 तक कर दी जाए ताकि वास्तविक निवेशकों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

ज्ञापन में इस बात पर जोर दिया गया कि अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण और तीन दशकों के बाद आतंकवाद में आई गिरावट ने निवेशकों में नई उम्मीद जगाई है और जम्मू-कश्मीर में एक व्यवहार्य निवेश गंतव्य के रूप में विश्वास बहाल किया है।

सीबीआई ने हिरासत में यातना मामले में जम्मू-कश्मीर के 8 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया; पुलिस रिमांड की मांग करेगी

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : सीबीआई श्रीनगर की विशेष अदालत से जम्मू-कश्मीर के आठ पुलिसकर्मियों की पुलिस रिमांड मांगेगी, जिन्हें उसने दो साल पहले एक साथी पुलिस कांस्टेबल पर झ्रूर और अमानवीय हिरासत में यातना देने के आरोप में गिरफ्तार किया था।

बुधवार रात विस्तृत पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए आठ अधिकारियों से आगे की पूछताछ की जाएगी ताकि कांस्टेबल खुशीद अहमद चौहान को झ्रग तस्करों की मदद करने के संदेह में छह दिनों तक प्रताड़ित करने में प्रत्येक आरोपी की भूमिका का पता लगाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर दर्ज अपनी प्राथमिकी में, केंद्रीय एजेंसी ने पुलिस उपाधीक्षक ऐजाज अहमद नायको और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जो उस समय संयुक्त पूछताछ केंद्र, कुपवाड़ा में तैनात थे। उन्होंने बताया कि जांच के दौरान, सीबीआई को चौहान के साथ कथित अमानवीय व्यवहार में सहायता करने और जांच में असहयोग करने के लिए दो और पुलिसकर्मियों की भूमिका का पता चला। उन्होंने बताया कि डीएसपी नायको के अलावा, सब-इंस्पेक्टर रियाज अहमद और छह अन्य को कथित आपराधिक साजिश और हत्या के प्रयास सहित अन्य आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। पीड़ित, जो बारामूला में तैनात था, को एक मादक पदार्थ मामले के संबंध में जांच के लिए कथित तौर पर कुपवाड़ा एसएसपी के सामने रिपोर्ट करने के लिए 17 फरवरी, 2023 को एक सिग्नल संचार के माध्यम से बुलाया गया था। आगमन पर, उन्हें संयुक्त पूछताछ केंद्र को सौंप दिया गया, जहां नाइको, रियाज अहमद और अन्य ने खुशीद को छह दिनों तक लोहे की छड़ और लकड़ी के डंडों से प्रताड़ित किया, इसके अलावा उसे भारी बिजली के झटके दिए और उसके जननांगों को विकृत कर दिया, पत्नी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया, जो अब एफआईआर का एक हिस्सा है। "अंत में 26 फरवरी, 2023 को खुशीद के गुप्तांग काट दिए गए, इसके अलावा उसके गुप्तांग में छह दिनों तक लगातार लोहे की छड़ें डाली गईं। खुशीद को गंभीर यातना दी गई और उसके मलाशय में लाल मिर्च डाली गई और बिजली के झटके भी दिए गए, "शिकायत में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामला सीबीआई को सौंपते हुए कहा था, उन्हें 26 फरवरी, 2023 को दोपहर 2.48 बजे एसकेआईएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ एक सब-इंस्पेक्टर उनके क्षत-विक्षत जननांगों को एक अलग प्लास्टिक बैग में अस्पताल ले आया था। यह एक ऐसा तथ्य है जो हमारी अंतरात्मा को झकझोर देता है। खुशीद की पत्नी, जो अपने पति के खिलाफ कथित अत्याचारों की जाँच के लिए दर-दर भटक रही थीं, की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन कुपवाड़ा एसएसपी, जिनके कहने पर पीड़ित को मादक पदार्थों के एक मामले में जाँच के लिए बारामूला से कुपवाड़ा भेजा गया था, भ्रूकदर्शक बने रहे। एजेंसी ने अपनी प्राथमिकी में एसएसपी को आरोपी नहीं बनाया है।

सीबीआई ने कुपवाड़ा में पुलिसकर्मी को प्रताड़ित करने के आरोप में अधिकारियों समेत 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दो साल पहले संयुक्त पूछताछ केंद्र कुपवाड़ा में एक पुलिस कांस्टेबल को कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में दो अधिकारियों सहित छह पुलिसकर्मियों और दो नागरिकों को आज गिरफ्तार किया।

कुपवाड़ा में एक पुलिस कांस्टेबल को कथित तौर पर हिरासत में प्रताड़ित करने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ये गिरफ्तारियां हुईं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और अवैध हिरासत के दौरान कांस्टेबल को लगी गंभीर चोटों के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया था। गिरफ्तार अधिकारियों में पुलिस उपाधीक्षक ऐजाज अहमद नाइकू, इंस्पेक्टर रेयाज अहमद, जहांगीर अहमद, इम्तियाज अहमद, मोहम्मद युनिस और शाकिर अहमद शामिल हैं। पुलिसकर्मी को प्रताड़ित करने के समय वे जेआईसी कुपवाड़ा में तैनात थे। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में पीड़ित के साथ हुए अमानवीय व्यवहार के लिए जवाबदेही और न्याय की मांग की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्रूरता की कड़ी निंदा की, जिसमें कांस्टेबल को लगी गंभीर चोटों पर प्रकाश डाला गया सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद दर्ज की गई प्राथमिकी में उल्लेख किया गया है कि शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस अस्पताल, सौरा, श्रीनगर के मेडिकल रिकॉर्ड में जननांगों का पूर्ण रूप से क्षत-विक्षत होना, दोनों अंडकोष निकाल दिए गए थे, अंडकोश पर घाव, हथेलियों और पैरों में कोमलता।

अरविंद गुप्ता ने भाजपा मुख्यालय में जन शिकायत शिविर लगाया, नागरिक विकास के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता दोहराई

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और जम्मू पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक अरविंद गुप्ता ने पार्टी मुख्यालय त्रिकुटा नगर, जम्मू में जन शिकायत शिविर का आयोजन किया। शिविर में विभिन्न इलाकों से आए प्रतिनिधिमंडलों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने अपने दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले नागरिक और विकासात्मक मुद्दों से संबंधित चिंताएँ व्यक्त कीं।

कई प्रतिनिधिमंडलों ने हाल ही में हुई लगातार बारिश के कारण नागरिक बुनियादी ढाँचे और सुविधाओं को हुए नुकसान के अलावा, खराब स्ट्रीट लाइटों, अनियमित पेयजल आपूर्ति, अपर्याप्त स्वच्छता, खस्ताहाल गलियों और

नालियों, और बार-बार बिजली कटौती की समस्याओं पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कई लोगों ने विधायक के साथ अपनी व्यक्तिगत चिंताएँ भी साझा कीं।

सभा को संबोधित करते हुए, अरविंद गुप्ता ने आश्वासन दिया कि उठाए गए हर मुद्दे को शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों के समक्ष उठाया जाएगा।

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भाजपा समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है। गुप्ता ने कहा, हमारी सरकार का ध्यान केवल बड़े पैमाने की परियोजनाओं पर ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर नागरिक बुनियादी ढाँचे को मजबूत करने पर भी है।

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक मोदी के भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं : वेद शर्मा

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : भाजपा जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेश के सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी वेद शर्मा ने भ्रष्टाचार या कदाचार में लिप्त पाए गए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को हटाने की व्यवस्था को सशक्त बनाकर सख्त जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विधेयकों के प्रस्तुतीकरण का स्वागत किया है।

आज यहाँ जारी एक बयान में, शर्मा ने कहा कि ये विधेयक भ्रष्टाचार मुक्त भारत निर्माण के सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे विधेयक लाने का कदम ऐतिहासिक है और पारदर्शिता तथा स्वच्छ शासन के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह एक स्पष्ट संदेश देता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका पद कितना भी ऊँचा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है।

विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए, शर्मा ने उन पर केवल निहित स्वार्थों को बचाने के लिए विधेयकों का विरोध करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, छन विधेयकों का



विरोध करके कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने अपनी मानसिकता उजागर कर दी है। उनकी आपत्ति से यह स्पष्ट होता है कि वे भ्रष्ट लोगों को बचाना चाहते हैं और भाई-भतीजावाद व पक्षपात की पुरानी व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं।

भाजपा के दृष्टिकोण पर प्रकाश डालते हुए, शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व

में देश ने शासन के हर स्तर से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निर्णायक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा, भाजपा हमेशा से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी में विश्वास करती रही है। ये विधेयक लोकतंत्र में लोगों के विश्वास को मजबूत करेंगे और सर्वोच्च पदों पर आसीन लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने नागरिकों से विपक्ष के दोहरे मानदंडों को समझने की अपील की। छशर्मा ने जोर देकर कहा, प्लोगों को यह पूछना चाहिए कि कोई ऐसे कदम का विरोध क्यों करेगा जो नेताओं को जनता के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने का प्रयास करता है। सच्चाई यह है कि भ्रष्टाचार कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकारों की पहचान रहा है, और उनका विरोध केवल स्वच्छ राजनीति के प्रति उनकी असहजता को दर्शाता है।

शर्मा ने दोहराया कि भाजपा एक पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए संघर्ष करती रहेगी, और विश्वास व्यक्त किया कि देश की जनता ऐसे सुधारों के साथ मजबूती से खड़ी है।

रामकृष्ण मिशन, इस शिविर के माध्यम से, आधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञता को पारंपरिक आयुर्वेदिक ज्ञान के साथ जोड़कर, सभी वर्गों के लोगों तक सुलभ स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने का प्रयास करता है।

खोख्याल गाँव में बाढ़ से प्रभावितों से मिले विधायक डॉ. भारत भूषण, हर संभव मदद का दिलाया भरोसा



पिछले दिनों हुए बाढ़ से नुकसान का जायजा लेने पहुंचे कटुआ विधायक डॉक्टर भारत भूषण । बाढ़ से प्रभावित स्कूल का भी किया दौरा

सबका जम्मू कश्मीर

कटुआ । कटुआ जिले में हाल ही में बाढ़ फटने और बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याओं का जायजा लेने

का सिलसिला जारी रखते हुए विधायक डॉ. भारत भूषण शुक्रवार को खोख्याल गाँव पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा और जरूरतों को

समझा तथा बाढ़ से हुए नुकसान का प्रत्यक्ष आकलन किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया कि प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सभी प्रभावित परिवारों को

हर संभव सहायता और राहत उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक ने कहा कि कठिन परिस्थितियों में सरकार और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह लोगों के साथ खड़े

हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी को भी परेशान नहीं होने दिया जाएगा और प्रभावित परिवारों की मदद व पुनर्वास के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे।

ड्रोन लुटेरों से फैली दहशत की हकीकत क्या?

ड्रोन की घटनाएं हकीकत हैं या अफवाह? ये अनसुलझी पहेली जैसा है। वैसे, पिछले दो सालों से 'स्वामित्व योजना' के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण भी ड्रोनो से करवा रही है। योजना मार्च-2026 तक पूरी होनी है। करीब 3 लाख 44 हजार गांवों का सर्वेक्षण होना है।

डॉ. रमेश ठाकुर



लगता है। सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में ड्रोन चोरों ने कुछ ज्यादा माहौल बिगाड़ा हुआ है। माहौल जैसे-जैसे बिगड़ना तेज हुआ, तो राज्य सरकार का ध्यान एकाएक उस ओर गया। मुख्यमंत्री ने तत्काल आपातकाल बैठक बुलाई।

हालांकि, उससे पहले ही अधिकारियों ने शासन को ड्रोन के संबंध में कुछ उत्पाती लोग उन्माद फैलाने की फिराक में होना दर्शा दिया था। शासन ने निर्णय लिया है कि ड्रोन के ज़रिए डर पैदा करने या गलत सूचना फैलाने वालों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाही की जाएगी।

लेकिन, शासकीय चेतावनी के बाद भी ड्रोन का उड़ना लगातार जारी है। दो दिन पहले भी मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में एक और उच्च-स्तरीय कानून-व्यवस्था को दुरुस्त करने को लेकर बैठक हुई, जिसमें बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाही का आदेश पारित हुआ। जिसके उलघन में कुछ यूट्यूबर और कैटरिंग वाले पकड़े गए। फिलहाल, पुलिस की पूछताछ में उनकी ड्रोन हरकतों में संलिप्ता नहीं मिली।

गौतललब है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में समय-समय पर किस्म-किस्म के चोर गिरोहों से अफवाहें फैलती रही हैं। चोटी कटवा, कच्छा-बनिया गिरोह, बाबा गिरोह, तलवारधारी गिरोह जैसे तमाम चोरों के गिरोह की सूचनाएं पूर्व में सुनने को मिलती रहीं। मौजूदा ड्रोन से जुड़ी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखंड और यूपी सरकार ने बकायदा पुलिस हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं।

जहां रात्रि के वक्त रोजाना सैकड़ों कॉल्स ड्रोन देखे जाने के संबंध में आ रही हैं। 7900 कॉल्स को पुलिस ने अभी तक रिकॉर्ड किया है जिसकी सत्यता पूरी तरह उन्माद से प्रेरित ही पाई गई। ड्रोन देखे जाने की सूचनाएं ज्यादातर अफवाहें ही साबित हो रही हैं जिनका किसी गिरोह से कोई संबंध फिलहाल दूर-दूर तक दिखाई नहीं देता? प्रशासन को 'ड्रोन लुटेरों' से फैली अफवाहों पर तुरंत अंकुश लगाना होगा, नहीं तो ग्रामीण ड्रोन गिरोह के सदस्यों के शक में बेकसूर लोगों को निशाना बनाते रहेंगे। बरेली में पिछले शनिवार को सबसे दर्दनाक घटना हुई, जहां मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति को 'ड्रोन गिरोह' का सदस्य समझकर लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला।

— डॉ. रमेश ठाकुर

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, भारत सरकार!
(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

'ड्रोन गिरोह' की अफवाहों ने शांति-व्यवस्था में खलबली मचा रखी है। विशेषकर ग्रामीणों में, जहां दहशत की स्थिति बनी हुई है। ड्रोन चारों के भय से लोग सारी-सारी रात जगे रहते हैं। प्रभावित दो-तीन राज्यों में करीब महीने भर से ड्रोन चोरा. के भय से लोग इतने भयभीत हैं कि वह रातों में जाग-जाग कर अपने घरों और परिजनों की पहरेदारी कर रहे हैं। डरे हुए लोग 'ड्रोन चोरों' को 'आसमानी चोर' कहने लगे हैं। आकाश में रात के वक्त सैकड़ों फीट उंचाई पर मंहराते रहस्यमय ड्रोनो से सन्नाटा इस कदर फैला है कि पेड़-पौधों के पत्तों की सरसराहट या झींगुरों की भिनभिनाहट मात्र से भी लोग डर जाते हैं। देखा जाए तो देहात क्षेत्रों में ड्रोन चोरों की अफवाहों का बाजार काफी समय से गर्म है। बढ़ती घटनाओं को देखते हुए पुलिस महकमा भी अलर्ट मोड़ पर है। रात में जायजा लेने को पुलिस-प्रशासन के आला अफसर भी ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस ने जागरूकता अभियान भी छेड़ रखा है। दरअसल, अफवाह लोगों की नासमझी से ज्यादा फैल रही है। ड्रोन दिखाई पड़ने पर वह पुलिस से संपर्क करने के बजाय सोशल मीडिया पर अना. पशनाप गलत सूचनाएं फैला देते हैं जिससे स्थिति और पैनिक हो रही है। हालांकि, ऐसे लोगों पर पुलिस सख्ती भी दिखा रही है।

ड्रोन की घटनाएं हकीकत हैं या अफवाह? ये अनसुलझी पहेली जैसा है। वैसे, पिछले दो सालों से 'स्वामित्व योजना' के तहत केंद्र सरकार ग्रामीण भूमि का सर्वेक्षण भी ड्रोनो से करवा रही है। योजना मार्च-2026 तक पूरी होनी है। करीब 3 लाख 44 हजार गांवों का सर्वेक्षण होना है। इसके पीछे सरकार का मकसद ग्रामीण संपत्ति के मालिकों को उनकी संपत्ति का मास्टर कार्ड वितरण करना है। 92 फीसदी कार्य 'ड्रोन मैपिंग' से पूरा हो चुका है

जिसमें 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं। सवाल ये भी उठता है क्या इस वक्त जो ड्रोन उड़ रहे हैं, वो इसी योजना का हिस्सा हैं? अभी तक कोई तथ्यात्मक सच्चाई मुकम्मल रूप से बाहर नहीं निकल पाई। जबकि, प्रथम दृष्टया प्रशासन ने ड्रोन घटनाओं को अफवाह ही माना है। ड्रोन की घटनाओं के पीछे कोई ऐसी हकीकत तो नहीं छिपी जिसे शासन-प्रशासन और सुरक्षा महकमा सार्वजनिक ना करना चाहता हो? राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ा तो कोई मसला नहीं? हालांकि ऐसे नाना-प्रकार के कयासों की मंडियां सजी हुई हैं। सच्चाई के असल नतीजों तक अभी कोई नहीं पहुंच पाया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तकरीबन जिलों में इस समय ड्रोन लुटेरों की ही चर्चाएं हैं।

धीरे-धीरे ये दहशत अब अन्य राज्यों में भी फैलती जा रही है। हरियाणा, पंजाब, बिहार, मध्यप्रदेश में भी आधुनिक चोरों से जुड़ी अजीबा. गरीब अफवाहें फैल गई हैं। बिहार के सासाराम और मध्यप्रदेश के गुना जिले में भी ड्रोन उड़ते देखे गए हैं। अफवाहें हैं कि चोर रात्रि में घरों का ड्रोन से सर्वेक्षण करते हैं और अगली रात धाबा बोलते हैं। एकाध घटनाएं घटी भी हैं, लेकिन उन घटनाओं से कोई हकीकत सिद्ध नहीं हुई। पुलिस-प्रशासन दोनों भी इस अनसुलझी पहेली में उलझे हुए हैं। प्रशासनिक स्तर पर ड्रोन की घटनाओं को बेशक अफवाह बताई जा रही हों। पर, ग्रामीण मानने को राजी नहीं? वह ड्रोन चोर या आसमानी चोर ही

माने बैठे हैं। बीते मात्र तीन हफ्तों में उत्तर प्रदेश में 365 और उत्तराखंड में 245 घटनाएं घटी हैं।

गौरतलब है कि अफवाहों के गर्भ से निकली ड्रोन चोरी की ये घटनाएं अब हिंसा में बदलने लगी हैं। गत दिनों बिजनौर के कोतवाली क्षेत्र में रात के वक्त एक खूनी घटना घटी जिसमें एक औरत का गला चाकू से रेतकर उसे जहर का इंजेक्शन देने का प्रयास हुआ। गनीमत ये रही कि उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया।

सुबह पुलिस ने छानबीन कर आसपास के लोगों से पूछताछ की, तो पता चला महिला पर हमला ड्रोन चोरों ने नहीं, बल्कि पड़ोसी ने किया जिनसे उनका पुराना जमीन विवाद चल रहा है। चोर समझकर अंधेरे में चलने वाले राहगीरों के साथ मारपीट की घटनाएं भी बढ़ी हैं। शराबियों की तो सामात ही आई हुई है। बिलावजह हादसे का शिक. ार न हो जाएं, इसलिए रात्रि पाली में काम करने वाले कर्मचारी भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसे भी घटनाएं खूब सामने आ रही हैं, जहां ड्रोन चोरों की आड़ में लोग अपनी पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हैं। दहशत और अफवाहें इस कदर देहर्तों में व्याप्त है कि आसमान में चमकती रौशनी को भी ड्रोन समझ कर अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है।

दहशत के चलते ग्रामीण पूरी-पूरी रात अपनी छतों पर बल्ब और टॉर्च जलाकर बैठे रहते हैं। जुगनुओं की रौशनी से भी चिल्ला पुकार मचने



तनाव में नरमी



संपादक - राज कुमार

चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली यात्रा एशिया के सबसे जटिल द्विपक्षीय संबंधों में से एक को फिर से स्थापित करने के एक सतर्क प्रयास का प्रतीक है। यह संपर्क इसलिए उल्लेखनीय है क्योंकि यह वर्षों की दुश्मनी के बाद हो रहा है, 2020 में गलवान घाटी में हुई घातक झड़पों के बाद, जिसने दोनों पक्षों के बीच बने नाजुक विश्वास को तोड़ दिया था। दोनों सरकारें अब यह मानती दिख रही हैं कि लंबे समय तक दुश्मनी उनके व्यापक रणनीतिक और आर्थिक हितों के खिलाफ है। श्री यी के संदेश के केंद्र में भारत और चीन से एक-दूसरे को प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि भागीदार के रूप में देखने का आह्वान था। उनके समकक्ष, विदेश मंत्री एस. जयशंकर का लहजा संयमित था, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट था कि संबंधों को एक कठिन दौर से आगे बढ़ना चाहिए। प्रतीकात्मकता महत्वपूर्ण है, लेकिन सार अधिक मायने रखता है। तीर्थयात्राओं की बहाली, नदी डेटा साझाकरण पर चर्चा, वीजा सेवाओं की बहाली, और यहाँ तक कि सीधी उड़ानें और सीमा व्यापार फिर से शुरू करने की संभावना। ये एक अस्थायी तनाव-मुक्ति के आधार स्तंभ हैं। चीनी पक्ष ने तो यहाँ तक दावा किया कि सीमा पर स्थिरता बहाल हो गई है। भारत के लिए, इस दावे को ज़मीनी हकीकतों के साथ तौला जाएगा, जहाँ अलगाव अभी भी अधूरा है और विश्वास बुरी तरह से कम हो गया है। फिर भी, यह मान्यता है कि नियंत्रित जुड़ाव आगे के टकरावों को रोकने में मदद कर सकता है। नई दिल्ली ने लगातार तर्क दिया है कि सीमा पर शांति सामान्य संबंधों के लिए एक पूर्वपेक्षा है। संचार के माध्यमों को फिर से खोलकर, दोनों पक्ष आधे रास्ते पर मिलने की इच्छा, हालाँकि ज़रूरी नहीं कि क्षमता, का संकेत देते हैं। इस मेल-मिलाप का समय आकस्मिक नहीं है। रूस के साथ दिल्ली के निरंतर ऊर्जा सौदों पर वाशिंगटन द्वारा लगाए गए दंडात्मक व्यापार उपायों के बाद, भारत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध एक अशांत दौर में प्रवेश कर गए हैं। ऐसे संदर्भ में, भारत एक कोने में सिमट कर रह जाने का जोखिम नहीं उठा सकता। हालाँकि चीन के बारे में उसकी दीर्घकालिक रणनीतिक चिंताएँ बनी हुई हैं, व्यावहारिक जुड़ाव उसे राहत प्रदान करता है और कूटनीतिक विकल्पों में विविधता लाता है। बीजिंग के लिए भी, बढ़ते वैश्विक अलगाव और धीमी होती घरेलू अर्थव्यवस्था के बीच भारत के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को संभालना आवश्यक है। फिर भी, सावधानी बरतना ज़रूरी है। पिछले अनुभव बताते हैं कि चीनी कूटनीति अक्सर स्थायी समझौते के बजाय सामरिक विराम चाहती है। इसलिए भारत को इस अवसर को मूल विवादों के समाधान के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सामरिक और आर्थिक क्षमताओं को मज़बूत करते हुए टकराव कम करने के एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। आगामी शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच संभावित मुलाकात पर कड़ी नज़र रखी जाएगी, लेकिन जब तक सीमा मुद्दे पर वास्तविक प्रगति नहीं होती, तब तक इसमें कोई सफलता मिलने की संभावना कम है। अंततः, भारत के सामने चुनौती यथार्थवाद और संयम के बीच संतुलन बनाने की है। चीन के साथ बातचीत ज़रूरी है, लेकिन बिना किसी भ्रम के। रिश्तों में स्थिरता संभव हो सकती है, लेकिन सच्चे विश्वास के लिए सिर्फ़ सोच-समझकर की गई यात्राओं से कहीं ज्यादा की ज़रूरत होगी। इसके लिए संप्रभुता के प्रति निरंतर सम्मान और ज़मीनी स्तर पर विश्वसनीय कार्रवाई की आवश्यकता होगी।

अपराधियों से निपटने में विफल नीतिश सरकार देगी हथियार लाइसेंस

योगेंद्र योगी

राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इससे बेशक राज्य का चाहे कितना ही नुकसान क्यों ना हो। बिहार जैसा प्रदेश जो एक दौर में नस्लवाद और जातीय हिंसा के लिए कुख्यात रहा, अब भी अपराधों के मामले में पीछे नहीं है। बिहार में सत्ता में कोई भी राजनीतिक दल रहा हो, अपराधों से सभी का गहरा रिश्ता रहा है। बिहार में कानून-व्यवस्था हमेशा से एक चुनौती रही है। हालात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इसका सरकार ने आसान विकल्प खोज लिया है। वह यह है कि अब मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य जैसे जनप्रतिनिधि आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस हथियार रख सकेंगे। जिससे लगभग ढाई लाख जनप्रतिनिधियों को फायदा मिलेगा। राज्य के गृह विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को इस संबंध में आवेदनों की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश जारी किया है। बिहार में आगामी चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतिश सरकार के इस फैसले को चुनाव से जोड़ कर देखा जा रहा है।

बिहार सरकार ने यह फैसला राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों पर हमले और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं के कारण लिया है। इसके विपरीत सच्चाई यही है कि ऐसा करके नीतिश सरकार ने ग्रामीण जनप्रतिनिधियों को साधने की कोशिश की है। यदि नीतिश कुमार के इस फैसले को पंचायत प्रतिनिधियों की सुरक्षा के हित में भी माना जाए तब यह प्रदेश में अपराध की हालत को दर्शाता है। जिस प्रदेश में जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं हैं, वहां आम अवाग की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। सवाल यह भी है कि लाखों की संख्या में हथियारों के लाइसेंस देने से क्या राज्य में हिंसा में बढ़ोतरी नहीं होगी। बिहार में यदि पुलिस तंत्र प्रभावी और मजबूत होता तो यह नौबत नहीं आती कि लाखों जनप्रतिनिधियों को हथियारों के लिए लाइसेंस दिया जाए। इससे जाहिर है कि मुख्यमंत्री नीतिश ने अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के बजाए हथियारों के लाइसेंस देने का आसान विकल्प चुना है। बड़ा सवाल यह भी है कि जनप्रतिनिधि अपनी सुरक्षा हथियारों से कर लेंगे, किन्तु प्रदेश की अवाग का क्या होगा।

मुख्यमंत्री नीतीश का यह फैसला दर्शाता है कि बिहार में कानून-व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो चुकी है। बिहार पुलिस हिंसक अपराध के मामलों में आई तेजी है। बिहार में पिछले 10 वर्षों में राज्य में फर्जी शस्त्र लाइसेंस, अवैध बंदूक और गोला व बारूद की अनाधिकृत तौर पर बिक्री बढ़ी है और यह प्रदेश में बढ़ रही हिंसा की बड़ी वजह है। राज्य के अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने इस दिशा में एक अध्ययन भी किया है। बिहार पुलिस ने यह अध्ययन बिहार पुलिस के महानिदेशक विनय कुमार को सुपुर्द किया। पुलिस ने राज्य में हिंसक अपराधों में वृद्धि को सीधे तौर पर राज्य में अवैध हथियारों और गोला-बारूद की बढ़ती बिक्री से जोड़ा है और हत्या, फिरोती के लिए अपहरण, डकैती, लूट, बैंक डकैती और सड़क डकैती जैसे अपराधों के लिए इसे जिम्मेदार माना है। एनसीआरबी (राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो) के अनुसार, बिहार 2017 से 2022 के बीच हिंसक अपराधों के मामले में लगातार शीर्ष पांच राज्यों में शुमार रहा है। इस अध्ययन में यह बात सामने आई कि प्रति वर्ष पटना में 82 हिंसा के मामले औसतन रूप से सामने आए हैं और राज्य की राजधानी हिंसा की राजधानी बन चुकी है। पटना के बाद क्रमशः मोतिहारी में 49.53, सारण 44.08, गया 43.50, मुजफ्फरपुर 39.93 और वैशाली में 37.90 मामले प्रति वर्ष औसतन दर्ज किए जा रहे हैं। हिंसक अपराधों की सबसे अधिक संख्या वाले शीर्ष 10 जिलों में पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, नालंदा और बेगूसराय शामिल हैं। ये उन शीर्ष 10 जिलों में से भी हैं जिनमें सबसे अधिक आर्म्स एक्ट के मामले हैं। अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अवैध आग्नेयास्त्र और हिंसक अपराध के मामलों के बीच घनिष्ठ संबंध है। एक दशक के अपराधों के अध्ययन के आधार पर विशेष कार्य बल ने बिहार के डीजीपी से सिफारिश की है कि वे व्यक्तिगत गोला-बारूद कोटा को मौजूदा 200 से घटाकर न्यूनतम कर दें। साथ ही यह भी सिफारिश की गई है कि डीजीपी कार्यालय आग्नेयास्त्रों का उपयोग करने में

बिहार की राजनीति और सत्ता लंबे समय से अपराध और हिंसा से जुड़ी रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार अपराध रोकने में नाकाम साबित हुई है और अब पंचायत प्रतिनिधियों को आत्मरक्षा हेतु हथियारों के लाइसेंस देने का फैसला लिया है। राज्य में ढाई लाख से अधिक जनप्रतिनिधियों को इसका लाभ मिलेगा। यह निर्णय पंचायत प्रतिनिधियों पर बढ़ते हमलों के बहाने लिया गया, मगर इसे चुनावी रणनीति माना जा रहा है। सवाल यह है कि हथियार बांटकर क्या अपराध घटेंगे या हिंसा और बढ़ेगी। एनसीआरबी और पुलिस अध्ययनों के अनुसार बिहार हिंसक अपराधों में शीर्ष राज्यों में शामिल है और अवैध हथियारों की बढ़ती बिक्री इसका बड़ा कारण है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में अपराध दर लगातार ऊँची बनी हुई है। महिला अपराधों और उत्पीड़न के मामलों में भी वृद्धि दर्ज हुई है। भ्रष्टाचार से पहले ही बदनाम बिहार में अब हथियारों की संस्कृति को बढ़ावा देना भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय है।

असमर्थ मानता है, उनके लाइसेंस रद्द कर दे। लाइसेंस प्राप्त मिनीगन कारखानों की निगरानी करें। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत में अपराधों के मामलों में शीर्ष पर उत्तर प्रदेश रहा। इसके बाद अपराधों के पायदान पर क्रमशः केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार है। अपराधों की श्रेणी में चोरी के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर डकैती और उत्पीड़न के मामले सामने आए। अपराधों में आंकड़ों के लिहाज से तीसरे नंबर बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। इस मामले में चिंता की बात यह है कि इसमें वर्ष 2023 के मुकाबले 1.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जबकि अपहरण के मामलों में पिछले वर्ष के मुकाबले 5.1 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

बिहार सरकार द्वारा जारी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ किए गए अपराधों से संबंधित दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 2021-22 में क्रमशः 13.05 प्रतिशत और 19.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021-22 में दर्ज सभी मामलों में से घरेलू हिंसा के लिए सबसे ज्यादा 4,889 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद दहेज उत्पीड़न (787), यौन उत्पीड़न (116), दूसरी शादी (81), मोबाइल/साइबर से जुड़े अपराध (59), बाल विवाह (24), कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (22), मानव तस्करी (12), दहेज हत्या (5) और अन्य (1,297) दर्ज किए गए। 2021-22 में 86 प्रतिशत दर्ज मामलों का निपटारा किया गया, जबकि 2020-21 में यह 82 प्रतिशत था।

बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने आंकड़े और आबादी के आधार पर दावा किया है कि 2004 के मुकाबले 2025 में अपराध में भारी गिरावट आयी है। लालू सरकार के काल खंड से तुलना करते हुए डीजीपी ने कहा कि 20-21 साल पहले सालाना 500-1000 फिरोती के लिए अपहरण के मामले दर्ज होते थे। अब यह आंकड़ा 50 के आसपास है। डकैती के मामलों में भी पहले 1200 से अधिक वार्षिक घटनाएँ होती थीं, जो अब घटकर 150 के करीब पहुंच चुकी हैं। गौरतलब है कि बिहार पहले से ही भ्रष्टाचार को लेकर बदनाम रहा है। लालू सरकार के चारा और जमीन के बदले में रेलवे में नौकरी को लेकर लालू यादव जेल में हैं। नीतिश कुमार से उम्मीद थी कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराधों में सुधार होगा। किन्तु जिस तरह हथियारों की संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बिहार का भविष्य उज्ज्वल नजर नहीं आता।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

प्रसिद्ध-प्राचीन ऐतिहासिक शंकराचार्य मन्दिर कश्मीर (श्रीनगर)

बलविंदर बालम

शंकराचार्य मन्दिर श्रीनगर से 4 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर दर्शनीय स्थान है। यह मन्दिर श्रीनगर के प्रत्येक भाग से देखा जा सकता है और इसकी ऊंचाई 1000 फुट है। इस मन्दिर की चोटी से सारा श्रीनगर (कश्मीर) नज़र आता है। दूर-दूर पहाड़ियों के बीच तथा डल झील का भव्यता तथा विशालता को आर्शीवाद देता हुआ आध्यात्मिकता का पर्याय हो जाता है। डल झील में शिकारे में बैठकर भी इस मन्दिर का अद्भुत नज़ारा देखा जा सकता है। पहाड़ी के सिर पर शोभनीय मन्दिर दूर से केवल ऊपरी भाग तक ही नज़र आता है। इस मन्दिर में शंकराचार्य की मूर्ति शोभनीय है साथ उनका एक ग्रंथ भी पड़ा हुआ है। मन्दिर में तथा अलग एक छोटे से तप कमेरे में उनकी मूर्तियां शोभनीय हैं। इस मन्दिर पर खड़े होकर आप सारे शहर का दृश्य देख सकते हैं। यहां जाने के लिए दो रास्ते हैं एक जो दुर्गानाग तथा गुएन,ओ

दफ़तर से जाता है और 3) कि.मी. की चढ़ाई है। इस रास्ते से जाकर आपको एक विशेष आनन्द मिलेगा और सैर भी हो जाएगी और रास्ते में आप डल झील, चार मिनार, मुगल बागों का दृश्य भी देखते रहेंगे।

गोपादरी या गुपकार टीले को शंकराचार्य का तख्ते-सुलेमान भी कहते हैं। समुद्रतल से 6240 फुट ऊंची यह पहाड़ी श्रीनगर के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके साथ ही जबवान पहाड़ियां नीचे डल झील उत्तर में जेतनाग और दक्षिण में जेहलम नदी है। यह मन्दिर डोरिक निर्माण पद्धति के आधार पर पत्थरों का बना हुआ है। इसके संबंध में कई विद्वानों का कहना है कि इसकी नींव ई. 200 पूर्व अशोक के सुपुत्र महाराजा जन्तूक ने डाली थी। इसकी मरम्मत समय-समय पर यहां के कई राजाओं ने की है। तथापि वर्तमान मन्दिर सिख राजकाल के राज्यपाल शेख मुहीउद्दीन की देन है। इन्होंने ही यहां शिवलिंग स्थापित किया और इस मन्दिर को शंकराचार्य मन्दिर कहे जाना लगा है। इस नये मन्दिर के निर्माण का आदेश उस समय के महाराजा रणजीत सिंह ने दिया था। उनके राज्यकाल में हिन्दु सिक्ख और मुसलमान में कोई भेद नहीं होता था और सब धर्मों का एक समान आदर होता था। इसके संबंध में यह भी मत है कि सन् 820 ई. में चौथे शंकराचार्य ने कश्मीर आकर इसी पहाड़ी पर तपस्या की थी। दुर्गानाग की तरफ से महाराजा गुलाब सिंह ने सन् 1925 ई. में इस मन्दिर तक पहुंचने के लिए पत्थरों की 41 सीढ़ियां बनवाई थीं। दूसरी सड़क नेहरूपार्क से जाती है और 5 मि.मी. लम्बी है। आप बस या टैक्सी से सड़क के द्वारा मन्दिर तक जा सकते हैं। सन् 1974 में यहां टेलीविजन टॉवर लग गया था और बहुत से सैनिक कैम्प लग गए हैं। सैनिक कैम्पों की फोटो न खिंचें तो अच्छा रहेगा। यहां के दर्शन करने के लिए आप शाम 6 बजे से पहले ही जाएं। रात को ऊपर नहीं जाने दिया जाता।

विद्वानों के अनुसार शंकराचार्य का समय 788 ई. से 820 तक है। इस मत की उद्भावना और पुष्टि का श्रेय डा. के.बी. पाठक को है। उन्होंने अनेक प्रमाणों द्वारा अपने मत की पुष्टि की है। शंकर के जन्म के अवसर पर प्रसिद्ध ज्योतिषियों का आगमन हुआ। शिव गुरु ने नवजात शिशु की कुण्डली उन्हें दिखलाई। उन्होंने कुण्डली का फल बताते हुए कहा, हे विद्वान, यह बालक सर्वगुण सम्पन्न और सर्वज्ञ होगा। यह स्वतन्त्र दार्शनिक सिद्धांत (अद्वैत मत) का प्रतिष्ठाता होगा और बड़े-बड़े मानी और प्रतिष्ठित पंडितों को शास्त्रार्थ में पराजित करेगा। जब तक पृथ्वी है, तब तक इसकी कीर्ति अमर रहेगी। हम लोग इसके सम्बन्ध में और अधिक क्या कहें, यह सभी दृष्टियों से परिपूर्ण होगा।

शिवगुरु ने इस शिशु का नामकरण किया – शंकर। बहुत कुछ सोच समझ कर उन्होंने यह



सार्थक नाम रखा था। पहले तो यह बालक सभी को आनन्द (सम) प्रदान करने वाला (कर) था और दूसरे यह कि इसकी उत्पत्ति शंकर जी की कठिन आराधना के फलस्वरूप उनके वरदान के कारण हुई थी।

जब वैदिक धर्म की दुर्दशा होने लगी, स्वर्ग दुर्गम हो गया, मोक्ष दुष्प्राप्य हो गया, प्राणधारी जीवों के स्वभाव मलीन हो गए, अमानवता का बोलबाला होने लगा, समस्त जगत में विघ्न-बाधा-रोग आदि ने डेरा डाल दिया, तब इस भूतल पर वैदिक धर्म की पुनः स्थाना के लिए भगवान महादेवा आचार्य शंकर के रूप में अवतरित हुए। उस समय आचार्य शंकर के आविर्भाव की महान आवश्यकता थी। यदि उनका अवतरण उस समय न हुआ होता, तो न जाने वैदिक धर्म किस पाताल के गहरे गर्त में गिरकर समाप्त हो गया होता। शंकर के जन्म का यही रहस्य है।

बालक शंकर ने आयु के प्रथम वर्ष में ही सभी अक्षरों तथा अपनी मातृ-भाषा मलयालम को सीख लिया। द्वितीय वर्ष में विधिवत पढ़ना सीख लिया और तृतीय वर्ष में काव्य और पुराणों को श्रवण मात्र से ही समझ लिया। शंकर बाल्यकाल से ही श्रुतधर थे, अर्थात् एक बार की सुनी हुई वस्तु, उनके मानस पटल पर सदैव के लिए अंकित हो जाती थी। तृतीय वर्ष में उनका चूड़ाकरण संस्कार सम्पन्न हुआ। शंकर के पांचवें वर्ष में, उनकी माता विशिष्टा ने सुन्दर योग और शुभ मुहूर्त में उनका उपनयन संस्कार शास्त्रीय विधि से सम्पन्न कर दिया। उपनयन संस्कार के पश्चात् शंकर विद्याध्ययन के लिए गुरु के समीप भेजे गए। उन्होंने अल्पकाल में अपने गुरु से चारों वेदों और षट् शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। शंकर ने ब्रह्म-विचार से विषयों की समस्त स्पृहाओं को नष्ट कर दिया। अपनी अनुपम शान्ति से उन्होंने परुषता, कठोरवाणी, हिंसा तथा क्रोध पर विजय प्राप्त की, सन्तोष द्वारा उन्होंने दीनता, परिग्रह भाषण एवं लोभ आदि का शमन किया। अद्वेष से मात्सर्य को जीत लिया। अपने अन्य उत्कृष्ट गुणों द्वारा मद तथा अहंकार का नाश किया। तृप्ति रूपी गुणों से तृष्णा रूपी पिशचिनी का संहार किया। कवि-शिरोमणि शंकर की अद्भुत वाणी के समक्ष शेष शारदा की वाणी भी मन्द पड़ जाती थी। उनकी वाणी चित्तरूपी उन्मत्त गज को बांधने के लिए मजबूत जंजीर है। सात वर्ष की अल्पायु में महा यशस्वी ब्रह्मचारी बालक शंकर वेदादिक समस्त शास्त्रों में पारंगत होकर प्रकाण्ड पण्डित हो गए। पूर्व पुण्य समूह से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ यतिवशों द्वारा वन्द्य यतिवार शंकर अन्तिम आश्रय संन्यास धारण कर उसी प्रकार सुशोभित हुए। अब शंकराचार्य ने आश्रम के अध्यापन कार्य का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। वहां के शिष्य वृन्द और अन्य विद्वान उनसे अध्ययन करने लगे। वे सभी शास्त्रों में पारंगत थे। शिवपुरी (वाराणसी) में रहकर इस महत्वपूर्ण भाष्य की रचना करना कठिन था, वहां उनकी अधिक प्रसिद्धि हो गई थी। पंडितों, शास्त्रार्थियों, जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं के झुण्ड उनके पास पहुंचने थे। वे निरन्तर लोकहित में निरत रहते थे। ब्रह्मसूत्र आदि पर भाष्य लिखकर आचार्य शंकर ने श्रुति के अर्थ और रहस्य का उद्धार

किया।

आचार्य शंकर ने व्यासगुफा में रहकर चार वर्षों में लिखने का सारा कार्य समाप्त कर दिया। यह उनके जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अब उनकी आयु सोलह वर्ष के समीप पहुंच रही थी। उनके शिष्यों ने आचार्य का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि जन-साधारण में भाष्यादि का प्रचार करना नितांत आवश्यक है। उन्होंने अपनी स्वीकृति दे दी। अतः वे अपने शिष्यों सहित सबसे पहले हिमालय के तीर्थों की यात्रा पर निकले। आचार्य शंकर और कुमारिल भट्ट की भेंट भारत के धार्मिक इतिहास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण घटना है। भट्टपाद कुमारिल में महा-प्रयाण के पश्चात् आचार्य शंकर ने शिष्यों सहित प्रयाग से प्रस्थान किया। मंडन मिश्र में शीघ्र मिलने के लिए उन्होंने योगशक्ति से आकाश का सहारा लिया। अंततः यतिशिरोमणि आचार्य शंकर ने अपनी युक्ति, तर्क, पांडित्य और अनुभव से विचक्षण मंडन मिश्र के शास्त्र-कौशल के सभी पक्षों का विधिवत खण्डन कर दिया। आचार्य शंकर ने श्रीशैल में निवास करके कापालिकों का प्रभुत्व कर वैदिक धर्म की पूरी-पूरी प्रतिष्ठा कर दी। ब्यास-रचित ब्रह्मसूत्र को वेदान्त-सूत्र या शरीरिक सूत्र भी कहा जाता है। इस ब्रह्मसूत्र में विशेषतया जीव के बन्धन और उसके मोक्ष लाभ का दार्शनिक विवेचन प्रस्तुत किया गया है। सामान्य व्यक्ति को उनके छोटे-छोटे सूत्रों का अर्थ समझना नितांत कठिन है। आचार्य शंकर ने इस कठिनाई को अनुभव करके उन सूत्रों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अद्वैतपरक भाष्य की रचना की। उनकी यह कृति दार्शनिक-जगत की अनुपम और अत्यन्त महात्वपूर्ण रचना मानी जाती है। ब्रह्मसूत्र, उपनिषदों और श्रीमद्भगवद्गीता पर भाष्य लिखना, श्रृंगेरी मठ का संस्थापन तथा अपने शिष्यों द्वारा वेदान्त-ग्रन्थों की रचना कराना आचार्य शंकर के महत्वपूर्ण कार्य थे। बारह वर्ष पूर्व आचार्य शंकर परिव्राजक के रूप में वाराणसी आए थे। तब वे अज्ञात बालक संन्यासी मात्र थे। अब उनका दूसरा ही स्वरूप हो गया था। समस्त भारत में उनकी कीर्ति की धवल गाथा व्याप्त हो गई थी। जन-जन के मुख पर उनका नाम था। आचार्य शंकर जिस प्रकार अध्यात्म विद्या, अद्वैत सिद्धान्त और शास्त्रों के प्रकाण्ड पंडित थे, उसी प्रकार जगत् के व्यवहार पक्ष के सम्पादन में भी पूर्ण निष्णात थे। उन्होंने अपनी पैनी दृष्टि से यह भलीभांति देख लिया था कि जो व्यक्ति सांसारिक उत्तरदायित्व के सम्पादन में निरत हैं, उनके ऊपर धर्म-प्रचार का कार्य नहीं सौंपा जा सकता। इसीलिए उन्होंने संसारत्यागी, विरक्त, निस्पृह, विद्वान्, सुयोग्य, ब्रह्मपरायण संन्यासियों के ऊपर धर्मप्रचार का कार्य सौंपा। दशनामी सम्प्रदायरु दशनामी संन्यासी सम्प्रदाय भी आचार्य शंकर के साथ समबद्ध है। शं. राचार्य के प्रभुत्व की छाप से कोई भी धार्मिक सम्प्रदाय बन ना सका। इस सम्प्रदाय के महन्तों के पास अतुल सम्पत्ति है। लोकोपकार में भी उस सम्पत्ति का कुछ अंश व्यय होता है। दशनामी का शब्दिक अर्थ है, दश नाम को धारण करने वाला। ये देश नाम इस प्रकार हैं। तीर्थ, आश्रम, वन, अण्य, गिरि, पर्वत,

सागर, सरस्वती, भारती, और पुरी। इन उपधियों (पदवियों) की कल्पना नितांत आध्यात्मिक है। इसकी व्याख्या आचार्य शंकर ने अपने मठाम्नाय में भलीभांति भलीभांति की है। दशनामी सम्प्रदाय के अखाड़ों में 52 मढ़ी बताई जाती है और मुख्यत पांच या छः अखाड़े हैं। प्रसिद्ध अखाड़ों के नाम इस प्रकार हैं। (1) पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी (प्रयाग) (2) पंचायती अखाड़ा निरंजनी (प्रयाग) (3) अखाड़ा अटल (4) जूना अथवा भैरव अखाड़ा (5) अखाड़ा आनन्द (6) अखाड़ा अग्नि (7) अखाड़ा अमान इस अखाड़े में बड़े शूरवीर हो गए हैं, जिन्होंने समय-समय पर हिन्दू धर्म की रक्षा विधर्मियों से की है। दशनामियों के मण्डलेश्वर बड़े विद्वान्, सदाचारी, नैष्ठिक तथा आत्मवेत्ता होते आए हैं। आज भी उनकी विद्वत्ता की धाक मानी जाती है। संन्यासियों की ये व्यापक संस्थाएं आचार्य शंकर की दूरदर्शिता को भलीभांति सिद्ध करती हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों को हम चार भागों में बांट सकते हैं— (क) भाष्य ग्रंथ (ख) स्तोत्र ग्रंथ (ग) प्रकरण ग्रंथ (घ) तंत्र ग्रंथ। भाष्य ग्रंथों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है – (अ) प्रस्थानत्रयी का भाष्य और (ब) इतर ग्रंथों के भाष्य।

आचार्य शंकर के वेदान्त मतानुसार व्यष्टि और समष्टि में कोई अन्तर नहीं है। व्यष्टि का अभिप्राय है व्यक्ति विशेष का शरीर और समष्टि का आशय है समूहात्मक जगत। वेदान्त तीन प्रकार का शरीर मानता है – स्थूल सूक्ष्म और कारण। इसके अभिमानी जीव के तीन नाम हैं। स्थूल शरीर का अभिमानी जीव विश्व, सूक्ष्म का अभिमानी तैजस तथा कारण का अभिमानी प्राज्ञ कहा जाता है। इसी प्रकार समष्टि के स्थूल शरीर के अभिमानी को विराट (वैश्वानर), सूक्ष्म के अभिमानी को सूत्रात्मा (हिरण्यगर्भ) और समष्टि के कारण शरीर के अभिमानी को ईश्वर कहा जाता है। अद्वैत वेदांत के अनुसार व्यष्टि और समष्टि के अभिमानी पुरुष सर्वथा अभिन्न हैं। आत्मा इन तीनों से स्वतंत्र सत्ता है। अद्वैतसिद्धान्त के प्रतिपादन के लिए आचार्य शंकर तीन सत्ताएं स्वीकार करते हैं— (1) प्रतिभासिक सत्ता (2) व्यावहारिक सत्ता और (3) पारमार्थिक सत्ता। आचार्य शंकर मायावाद के व्यवस्थापक थे और जगत को मायिक तथा स्वप्नवत मानते थे। आचार्य शंकर उद्भट पंडित थे। उनमें विशेषता यह थी – एक बार भी जो अध्ययन अथवा श्रवण कर लेते थे, वह सदैव के लिए उनके मानस पटल पर अंकित हो जाती थी। उन्होंने तीन वर्ष की अल्पायु में अपनी मातृभाषा, मलयालम का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था, आठ वर्ष की आयु में वे समस्त वेदों में पारंगत हो गए थे और सोलह वर्ष की आयु में उन्होंने प्रस्थानयी (उप-निषद्, ब्रह्मसूत्र और श्रीमद्भगवद्गीता) पर विलक्षण भाष्य रचना की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने उनके संबंध में अपना उद्गार इस प्रकार अभिव्यक्त किया है, इस सोलह वर्ष के बालक के लेख से आधुनिक सभ्य जगत विसिप्त हो गया है।

बलविंदर बालम गुरदासपुर
ऑकार नगर गुरदासपुर (पंजाब)

उच्च स्तरीय कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कठुआ में राहत शिविरों का दौरा कर प्रभावित परिवारों से की मुलाकात, मांगा विशेष राहत पैकेज



बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित कठुआ जिले के विभिन्न राहत शिविरों का जम्मू-कश्मीर कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल दौरे की तस्वीरें

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, 19 अगस्त बादल फटने और अचानक आई बाढ़ से प्रभावित कठुआ जिले के विभिन्न राहत शिविरों का जम्मू-कश्मीर कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने दौरा किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके पुनर्वास एवं मुआवजे की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कार्यकारी अध्यक्ष

रमण भल्ला ने किया, जबकि उनके साथ पूर्व सांसद चौधरी लाल सिंह, पूर्व विधायक ठाकुर बलबीर सिंह, मुख्य प्रवक्ता रविंदर शर्मा, पूर्व मंत्री यशपाल कुंडल, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कठुआ पंकज डोगरा, जिला अध्यक्ष जम्मू ठाकुर मनमोहन सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

नेताओं ने प्रभावित लोगों को भरोसा दिलाया कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और केंद्र व केंद्रशासित प्रदेश सरकार से उचित राहत और पुनर्वास

सुनिश्चित करवाने के लिए संघर्ष करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से विशेष पैकेज की मांग करते हुए कहा कि जिन परिवारों ने अपने परिजन खोए हैं उन्हें 10 लाख रुपये का मुआवजा, वैकल्पिक जमीन और आश्रय दिया जाए ताकि उनके जीवन-यापन की गारंटी हो सके।

कांग्रेस नेताओं ने मगर खड्ड क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के पास सुरक्षा दीवार में आई दरारों पर भी गंभीर चिंता जताई और प्रशासन से तत्काल सुरक्षा कदम उठाने की अपील की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस

अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष तारिक हमीद करी की ओर से भी शोक संवेदना प्रकट की। प्रेस वार्ता एवं दौरे में राकेश चौधरी, संजीव पांडा, परमजीत सिंह, निर्दोष शर्मा, विजय चौधरी, जतिन वशिष्ठ, रमण ठाकुर, नरेंद्र खजूरिया, तरसेम सिंह सैनी, सतपाल भंडारी, योगराज, विष्णु अन्डोत्रा, विनय कुमार, सोहन लाल, रमेश कुंडल, प्रदीप भल्ला, वेद राज शर्मा, कैप्टन अंचल भगत, यशपाल सहित अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे।

आजादी के 78 वर्षों में कितने बदले लोकतंत्र के हालात?

ऐसे बदरंग हालातों में यह सवाल रह-रहकर सिर उठाने लगता है कि आखिर कैसी है ये आजादी? आखिर आजादी का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि यह न जान लिया जाए कि स्वतंत्र होना आखिर कहते किसे हैं?

योगेश कुमार गोयल



भी चांदी हो चली है। आजादी के बाद लोकतंत्र के इस बदलते स्वरूप ने आजादी की मूल भावना को बुरी तरह तहस-नहस कर डाला है। यह आजादी का एक शर्मनाक पहलू ही है कि गिने-चुने मामलों को छोड़कर हत्या, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसे संगीन अपराधों से विभूषित जनप्रतिनिधि अक्सर सम्मानित जिंदगी जीते रहते हैं। देश के ये बदले हालात आजादी के कौनसे स्वरूप को उजागर कर रहे हैं, विचारणीय है।

ऐसे बदरंग हालातों में यह सवाल रह-रहकर सिर उठाने लगता है कि आखिर कैसी है ये आजादी? आखिर आजादी का अर्थ क्या है? इस प्रश्न का उत्तर तब तक नहीं दिया जा सकता, जब तक कि यह न जान लिया जाए कि स्वतंत्र होना आखिर कहते किसे हैं? देश को? व्यक्ति को? समाज को? यह जानना भी जरूरी है कि क्या कुछ बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित व्यक्ति, समाज या देश को स्वतंत्र कहा जा सकता है? क्या भोजन, कपड़ा और रहने की व्यवस्था, बीमारी से बचाव, भय-आतंक, शोषण व असुरक्षा से छुटकारा, साक्षर एवं शिक्षित होने के पर्याप्त अवसर मिलना और अन्य ऐसी ही कई बातें मानव के बुनियादी अधिकार नहीं हैं? क्या शोषण और उत्पीड़न से मुक्ति के संघर्ष को मानव का बुनियादी अधिकार नहीं माना जाना चाहिए? लोकतंत्र के हाशिये पर खड़ी देश की जनता को इस दिशा में फिर से मंथन करना आवश्यक हो गया है कि वह किस तरह की आजादी की पक्षधर है? आज की आजादी, जहां तन के साथ-साथ मन भी आजाद है, सब कुछ करने के लिए, चाहे वह वतन के लिए अहितकारी ही क्यों न हो, या उस तरह की आजादी, जहां वतन के लिए अहितकारी हर कदम पर बंदिश हो। आज की आजादी, जहां स्वहित राष्ट्रहित से सर्वोपरि होकर देशप्रेम की भावना को लीलता जा रहा है, या वह आजादी, जहां राष्ट्रहित की भावना सर्वोपरि स्वरूप धारण करते हुए देश को आजाद कराने में गुमानम लाखों शहीदों के मन में उपजे देशप्रेम का जज्बा सभी में फिर से जागृत कर सके। इस तरह के परिवेश पर सभी देशवासियों को आजादी के इस पावन पर्व पर सच्चे मन से मंथन कर सही दिशा में संकल्प लेने की भावना जागृत करनी होगी, तभी आजादी के वास्तविक स्वरूप को परिलक्षित किया जा सकेगा।

प्रत्येक भारतवासी के लिए 15 अगस्त का दिन गौरव का दिन है क्योंकि इसी दिन भारत को अंग्रेजों की दासता से मुक्ति मिली थी। हालांकि स्वतंत्रता दिवस को लेकर आज भी देश के प्रत्येक नागरिक के दिलोदिमाग में वही जज्बा और उत्साह समाहित है लेकिन जब हर वर्ष स्वतंत्रता के प्रतीक तिरंगे के नीचे खड़े होकर बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधियों को देश की रक्षा व प्रगति का संकल्प लेते देखते हैं, जो वर्षभर सरेआम लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते देखे जाते हैं तो मन में यही सवाल उठता है कि आखिर ऐसी संकल्प अदायगी से देश को हासिल क्या होता है? देश को आजाद हुए सात दशक से अधिक हो चुके हैं लेकिन आजादी के इन 78 वर्षों में लोकतंत्र के पवित्र स्थल संसद और विधानसभाओं के हालात किस कदर बदले हैं, वह किसी से छिपा नहीं है, जहां अभद्रता की सीमा पार करते जनप्रतिनिधि गाली-गलौच, उठापटक से लेकर कुर्ता-फाड़ राजनीति तक उतर आते हैं। विधानसभाओं की तो क्या बात करें, जब संसद की कार्यवाही ही कभी विपक्ष और कभी स्वयं सत्ता पक्ष द्वारा ही कई-कई दिनों तक लगातार नहीं चलने दी जाए तो राष्ट्र के लिए इससे ज्यादा चिंतनीय स्थिति और क्या हो सकती है? संसद में होने वाले ऐसे हंगामों के कारण प्रति मिनट आम आदमी के करीब द्वाइ लाख रुपये बर्बाद होते हैं यानी हर एक घंटे में करीब डेढ़ करोड़ रुपये खर्च होते हैं। अब चूंकि संसद की कार्यवाही प्रतिदिन 6 घंटे चलनी होती है, ऐसे में संसद के दोनों सदनों में दोनों पक्षों के विरोध, हो-हल्ले और शोर के कारण जनता के

खून-पसीने की कमाई के प्रतिदिन करीब 9 करोड़ रुपये से अधिक बर्बाद हो जाते हैं।

गंभीर चिंतन का विषय है कि वर्षों की गुलामी के बाद मिली आजादी को आज हम जिस रूप में संजोकर रख पाए हैं, वह 78 वर्षों में ही कितना विकृत हो चुका है। आजादी के दीवानों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस देश को आजाद कराने के लिए वे इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं, वहां कुछ दशकों में ही आजादी की तस्वीर ऐसी हो जाएगी। हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश ने विकास के मार्ग पर तेजी से कदम बढ़ाए और विकास के अनेक सोपान तय किए हैं। तकनीकी कौशल हासिल करते हुए देश अंतरिक्ष तक जा पहुंचा है और चांद पर भी तिरंगा लहरा दिया है। लेकिन महिलाओं से दुर्व्यवहार की लगातार बढ़ती घटनाएं और समाज में अपराधों की बढ़ती सीमा को देख बुजुर्ग तो अब कहने लगे हैं कि गुलामी के दिन तो आज की आजादी से कहीं बेहतर थे, जहां अपराधों को लेकर मन में भय तो व्याप्त रहता था किन्तु कड़े कानून बना दिए जाने के बावजूद अपराधियों के मन में अब किसी तरह का भय नहीं दिखता। 'सैंयां भये कोतवाल तो डर काहे का' कहावत हर कहीं चरितार्थ हो चली है। देश के कोने-कोने से सामने आते अबोध बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों के बढ़ते मामले आजादी की बेहद शर्मनाक तस्वीर पेश कर रहे हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ जिस तरह की दरिदगी की गई है, ऐसे मामलों को देखते हुए

और क्या कहा जाए? देश में महंगाई सुरसा की तरह बढ़ रही है, आतंकवाद की घटनाएं पग पसार रही हैं, आरक्षण की आग रह-रहकर देश को जलाती रहती है। इस तरह के हालात निश्चित तौर पर देश के विकास के मार्ग में बाधक बनते हैं। हर कोई सत्ता के इर्द-गिर्द राजनीतिक रोटियां सेंकता नजर आ रहा है, कोई सत्ता बचाने में लगा है तो कोई गिराने में। संसद और विधानसभाओं में हंगामे आए दिन की बात हो गई है।

आजादी के बाद सामाजिक और आर्थिक पहलू पर देश में कमजोर तबके का स्तर सुधारने की नीयत से लागू आरक्षण के राजनीतिक रूप ने देश को आज उस चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां समूचा देश रह-रहकर जातीय संघर्ष के बीच उलझता दिखाई देता है। स्वार्थपूर्ण राजनीति ने माहौल को इस कदर विकृत कर दिया है, जहां से निकल पाना संभव ही नहीं दिखता। राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, हरियाणा हो या गुजरात अथवा महाराष्ट्र, आरक्षण के नाम पर उठते विध्वंसक आन्दोलनों की आग में से जब-तब बुरी तरह झुलसते रहे हैं और हर कोई इस तरह के परिवेश का राजनीतिक लाभ लेने की कवायद में जुटा नजर आता है। आजादी के बाद के इन करीब साढ़े सात दशकों में भ्रष्टाचार और अपराध इस कदर बढ़ गए हैं कि आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। बगैर लेन-देन के प्रायः कोई कार्य सम्पन्न नहीं होता।

बड़े नेता की तो कौन कहे, छुटभैया नेताओं की

डिविजनल कमिश्नर व आईजीपी जम्मू ने किया कटुआ के बादल फटने व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

पीड़ितों को त्वरित राहत व सेवाओं की बहाली का दिया आश्वासन



सबका जम्मू कश्मीर

कटुआ, डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार और इस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू बी.एस. टुटी ने आज कटुआ जिले के बादल फटने और फ्लैश फ्लड से प्रभावित भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा कर स्थिति का जायजा लिया और राहत व बहाली के कार्यों की समीक्षा की।

सिडको घाटी में स्थापित राहत शिविर में डिविजनल कमिश्नर ने जोड़े क्षेत्र के प्रभावित परिवारों से मुलाक.

त की, जहां हाल ही में पांच लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने विस्थापित परिवारों के साथ बातचीत की, गहरी संवेदना प्रकट की और हर संभव सरकारी मदद का आश्वासन दिया।

उन्होंने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से जिला प्रशासन द्वारा तत्काल वित्तीय सहायता दी गई है। साथ ही उन्होंने उपायुक्त कटुआ को प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क बहाल करने के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।

डिविजनल कमिश्नर ने दिलवान गांव का भी दौरा

किया, जहां बाढ़ के कारण सड़क ढांचे व रिहायशी क्षेत्रों को भारी नुकसान हुआ। उन्होंने पीडब्ल्यूडी, पीएचई और पीडीडी के कार्यकारी इंजीनियरों को आपसी तालमेल से काम कर प्रभावित परिवारों की मुश्किलें कम करने के लिए जल्द से जल्द बुनियादी सेवाएं बहाल करने के निर्देश दिए।

बाद में उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज कटुआ का दौरा किया और जाखोले व जंगलोट के घायल व्यक्तियों से मुलाकात की जो वहां उपचाराधीन हैं। उन्होंने उनकी सेहत और उपचार की जानकारी ली

तथा जीएमसी प्रशासन व जिला प्रशासन को घायलों व उनके परिजनों को बेहतर से बेहतर इलाज व देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

इस मौके पर डीआईजी जम्मू-सांबा-कटुआ रंज शिव कुमार शर्मा, एडीसी कटुआ विश्वजीत सिंह, संबंधित तहसीलदार सहित पीडब्ल्यूडी, पीएचई, पीडीडी व अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

फोटो कैप्शनरू- डिविजनल कमिश्नर कटुआ के बादल फटने व बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों का हाल जानते

हसौद में चोरी की घटनाएं बेकाबू, एक ही घर में दो बार चोरी - श्रद्धा मोबाइल के बाहर से बाइक भी उड़ा ले गए चोर



राज कुमार



सक्ती//जिले के हसौद नगर में चोरी की बढ़ती घटनाओं ने आम नागरिकों की नींद उड़ा दी है। बीते दिनों प्रेमलता भार्गव के घर में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाकर 20,000 रुपये नगदी चुरा ली थी। हैरानी की बात यह है कि इस घटना के एक सप्ताह बाद फिर से उसी घर को चोरों ने निशाना बनाया और ताले तोड़ दिए। इससे क्षेत्रवासियों में दहशत का माहौल है।

पीड़िता प्रेमलता भार्गव ने बताया, प्यहली चोरी के बाद हमने पुलिस से कार्रवाई की उम्मीद की थी, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। अब दूसरी

बार फिर से घर में चोरी हुई है। यह बेहद डराने वाली स्थिति है। परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है।

पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को पकड़ नहीं पाई है। जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इलाके में लगातार हो रही घटनाओं से लोगों का भरोसा डगमगाने लगा है।

इसी के साथ एक अन्य चोरी की घटना में, हसौद स्थित श्रद्धा मोबाइल दुकान के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल को चोरों ने पार कर दिया। यह पूरी वारदात दुकान के सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बावजूद इसके, चोर अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।

स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों का कहना है कि अगर सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी चोर नहीं पकड़े जाते, तो यह पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल है। श्रद्धा मोबाइल के संचालक ने बताया कि "हमने फुटेज पुलिस को दे दिया है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। दुकानदारी पर भी असर पड़ रहा है।"

इन घटनाओं ने क्षेत्र में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है। नागरिकों ने थाना प्रभारी और पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि इन मामलों की जल्द जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए और क्षेत्र में रात्रि गश्त को सख्त किया जाए।

पहले ना, अब हां... 130वें संविधान संशोधन पर बनने वाली जेपीसी में शामिल होगा विपक्ष

एजेंसी

गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और लगातार 30 दिन हिरासत में रखे गए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने से जुड़े प्रावधान वाले विधेयक को अब संसद की संयुक्त समिति (श्रच्चे) को भेज दिया गया है। विधेयक को लेकर विपक्षी सांसदों ने कड़ी आपत्ति जताई थी, लेकिन अब खबर है कि विपक्ष विधेयक पर चर्चा के लिए बनाए जा रही जेपीसी में शामिल होगा। संभावना यह भी है कि आज शाम तक समिति के सदस्यों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाए।

संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 समेत 3 विधेयकों को संसद में पेश किए जाने के बाद विपक्ष ने दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया था। विधेयक पर विपक्ष की नाराजगी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पर विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजने की बात कही थी। इसके बाद पहले लोकसभा फिर राज्यसभा ने विधेयक को जेपीसी के पास भेजने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी।

पहले विपक्ष कर रहा था विरोध

हालांकि पहले कहा जा रहा था कि संविधान संशोधन बिल पर बनने वाली जेपीसी में विपक्ष शामिल होने के पक्ष में नहीं है। कुछ विपक्षी दलों का कहना था कि संयुक्त संसदीय समिति में नहीं जाना चाहिए क्योंकि यह असंवैधानिक बिल है, लेकिन अब यह फैसला हुआ कि विपक्षी सांसद जेपीसी में शामिल होंगे। विपक्ष की ओर से जेपीसी में शामिल होने वाले सदस्यों के नाम आज ही ऐलान किए जा सकते हैं। जेपीसी में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल किए जाने हैं।

इससे पहले राज्यसभा ने आज गुरुवार को 3 विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को 30 दिन पूरा होने के बाद पद से हटाने का प्रावधान किया गया है।

शीतकालीन सत्र में आ सकती है रिपोर्ट

राज्यसभा में हंगामे के बीच गृह मंत्री शाह ने संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 को जेपीसी को विचार के लिए भेजने का प्रस्ताव किया। उन्होंने यह भी प्रस्ताव किया कि इस समिति में सदन के ऊपरी सदन के उपसभापति 10 सदस्यों को नामित करें।

आसमान में भारत की तीसरी आंख... अवाक्स से होगी दुश्मन की हर हरकत पर नजर

एजेंसी

भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना की हवाई निगरानी और कमांड क्षमताओं को बढ़ा बढ़ावा देते हुए अवाक्स इंडिया प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने लगभग 19,000 करोड़ रुपये की डील को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत एअरबस A321 विमान

पर आधारित 6 एयरबोर्न अल्टी वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम वायुसेना में शामिल किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व डीआरडीओ करेगा।

एयरबस विमान उपलब्ध कराएंगी और तकनीकी मदद देगी। भारत की कई सरकारी और निजी कंपनियां इसमें शामिल होंगी और सब-सिस्टम, सॉफ्टवेयर व ग्राउंड सपोर्ट बनाएंगी।

फिलहाल भारत के पास सिर्फ कुछ ही

आईडब्ल्यूएंडसी विमान हैं,

इनकी संख्या कम होने की वजह से पूरे देश के हवाई क्षेत्र पर 24x7 निगरानी रखना मुश्किल है। लेकिन अब नए ए321 आधारित आईडब्ल्यू एंड सी आने के बाद यह कमी पूरी हो जाएगी। भारत का यह कदम ऐसे समय पर आया है जब चीन के पास 30 से अधिक अवाक्स विमान मौजूद हैं।

साप्ताहिक राशिफल



मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको निजी जीवन से लेकर करियर-कारोबार तक में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज-मस्ती करते हुए बीतेगा। घर-परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर-कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।



वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर-कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल-मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटक कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर-परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन-जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी-साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।



मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतः दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक-कार्यों में खूब रहेगा। किसी धार्मिक-आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक. बले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।



कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते-नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।



सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुनी पड़ सकती है।



कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद-विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर-कारोबार से लेकर घर-परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।



तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते-नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर-कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी-रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।



वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता-सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर-कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर-परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन-पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।



धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता है। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।



मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार-चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर-कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात-व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आए अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि. कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर-कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।



कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी-मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल-मिलाप बढ़ेगा। आपके मान-सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।



मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी-रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि-भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है। ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग. लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा-पाठ में बीतेगा।

सीएम फडणवीस से मिले राज ठाकरे, 50 मिनट से ज्यादा चली बातचीत, क्या पक रही नई खिचड़ी?



एजेंसी

महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी हलचल तेज हो गई है. गुरुवार की सुबह को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (डब्ल्यू) के प्रमुख राज ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बीच बैठक हुई. राज ठाकरे सीएम से मिलने उनके वर्षा बंगले पर पहुंचे. इसी के बाद राज और फडणवीस की मुलाकात पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर फिर शुरू हो गया है. मीटिंग के बाद राज ठाकरे ने बताया कि उनकी सीएम से किन मामलों को लेकर चर्चा हुई.

राज ठाकरे और सीएम के बीच में हुई इस मुलाकात के समय को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं. दरअसल, हाल ही में ठाकरे बंधु राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर मराठी भाषा के मामले को लेकर साथ आए. लेकिन, अब राज ठाकरे ने सीएम फडणवीस से उस समय मुलाकात की है जब ठाकरे बंधु बीईएसटी कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी चुनाव में पूरी तरह से फेल हो गए. ठाकरे बंधुओं 21 में से एक भी सीट जीतने में नाकाम रहे.

किन मामलों पर हुई चर्चा?

राज ठाकरे ने सीएम से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बताया कि इस

मीटिंग में दोनों के बीच क्या-क्या चर्चा हुई. राज ठाकरे ने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी को मिला, मुंबई के ट्रैफिक समस्याओं को लेकर एक योजना पर बात की. इस बैठक में ट्रैफिक पुलिस के जॉइंट सीपी, अधिकारी भी मौजूद थे. मैंने ये रणनीति बताई की छोटे-छोटे मैदानों के नीचे 500 से 1000 गाड़ियों की पार्किंग पथ बनाया जाए.

उन्होंने आगे कहा, पार्किंग और नो पार्किंग के लिए अलग-अलग फुटपाथ के अलग-अलग रंग लगाए जाएं. ताकि लोगों को पता हो किस फुटपाथ किनारे गाड़ी लगाना चाहिए और कहा नहीं. मैंने इसको लेकर प्रेजेंटेशन दिया.

राज ठाकरे ने कहा, आज दुपहिया वाहन चालक सिग्नल सिस्टम का पालन नहीं करते, कानून का पालन नहीं करते. ऐसे में शहर के ट्रैफिक की समस्या दूर नहीं होगी. ये गैर जवाबदेही मुंबई को आगे बढ़ने नहीं देगी कैसे गाड़ी चलाना है, कैसे कहां पार्क करना है, कहां फेरीवालों को जगह देनी है, कहां नहीं इस सब बातों पर चर्चा हुई.

मुंबई की सड़कों पर बोले

आज मुंबई के सड़कों की क्या हालत है, लोग गड्ढों में गिरकर मर रहे हैं. यहां सड़क बनाने वाले ठेकेदार अलग हैं वो सड़क बनाते

ही इसलिए हैं क्योंकि सड़क खराब हो. इसके बाद आते हैं खराब सड़क को रिपेयर करने वाले ठेकेदार. बाद में आते हैं गड्ढा भरने वाले ठेकेदार. ये गड्ढा भरते कम है खोदते ज्यादा हैं. यह हालात हैं मुंबई के और सिर्फ मुंबई नहीं महाराष्ट्र के सभी शहरों-गांवों का यही हाल है.

लेकिन, जो बाहर से आ रहे हैं उन्हें उनके राज्य में अच्छे रोजगार के साधन बना कर देंगे तो वो मुंबई में आना बंद करेंगे और यहां जो झोपड़े बन रहे हैं वो बंद होंगे, मुंबई में बाहर से लोगों का आना जबतक बंद नहीं होगा यहां इस शहर की समस्या ऐसी ही बनी रहेगी.

50 मिनट चली मीटिंग

राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस की ये मीटिंग लगभग 50 मिनट से ज्यादा समय तक चली. महाराष्ट्र में जल्द ही निकाय चुनाव भी होने हैं. निकाय चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत और बाकी नेता यह बयान दे चुके हैं कि राज ठाकरे के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ सकते हैं. लेकिन, दूसरी तरफ मनसे प्रमुख की ओर से इस बात को लेकर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है. न खुद राज ठाकरे और न ही उनके किसी नेता ने यह कहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन होगा या साथ मिलकर आगामी चुनाव लड़े जाएंगे.

यह मुलाकात उस समय हुई है जब उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने पहली बार मिलकर बीईएसटी कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी के चुनाव लड़े थे, लेकिन बुधवार को उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी. शशांक राव के नेतृत्व वाली बीईएसटी वर्कर्स यूनियन पैनल ने 14 सीटें जीतीं, जबकि बीजेपी समर्थित पैनल (प्रसाद लाड और प्रवीण डेरेकर की अगुवाई वाला) ने 7 सीटें जीतीं.

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सरकारी आवास के लिए अभी तक नहीं किया संपर्क, ऐसी है शहरी विकास मंत्रालय की तैयारी



एजेंसी

देश के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से 21 जुलाई, 2025 को इस्तीफा दे दिया था. इस इस्तीफे के पीछे की वजह उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को बताया था. जगदीप धनखड़ इस समय उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में रह रहे हैं. इस्तीफे के बाद वे यहां करीब 15 महीनों तक रह सकते हैं. इस्तीफे के बाद भले ही धनखड़ ने नए बंगले को लेकर शहरी विकास मंत्रालय से संपर्क न किया हो पर विभाग ने पहले से ही उनके नए बंगले की व्यवस्था कर ली है.

पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अभी तक अपने लिए सरकारी आवास के लिए शहरी विकास मंत्रालय से अभी तक संपर्क नहीं किया है. लेकिन शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले डायरेक्टर ऑफ एस्टेट ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के लिए 34 एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग पर टाइप-8 का बंगला खाली करा लिया है.

विभाग की तरफ से कहा गया कि यदि जगदीप धनखड़ को 34 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर बंगला पसंद नहीं आता है, तो शहरी विकास मंत्रालय उनको दूसरे विकल्प दे सकती है.

पद छोड़ने के बाद किस तरह बंगला दिया जाता?

भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटने के बाद दिल्ली के लुटियन जोन में टाइप 8 या उनके पैतृक स्थान पर 2 एकड़ की भूमि दी जाती है. शुरुआती खबर के मुताबिक जगदीप धनखड़ को भी एक टाइप-8 सरकारी बंगला दिया जाएगा.

जगदीप धनखड़ पिछले साल अप्रैल में ही नवनिर्मित 'उपराष्ट्रपति एन्क्लेव' में शिफ्ट हुए थे, जो संसद भवन परिसर के पास चर्च रोड पर मौजूद है. ये एन्क्लेव सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाया गया था. अब इस्तीफे के बाद उन्हें यह आवास खाली करना होगा. हालांकि इसके लिए अभी समय है. इसके बाद विभाग उनके रहने के इंतजाम में लग गया है. जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति का पद खाली है. चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर पूरे चुनाव का शेड्यूल तैयार किया गया है. 21 तारीख तक उम्मीदवार अपना-अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं.



Helpline

पुलिस स्टेशन

बाग-ए-बहू	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	2575151
छहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिममत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी छहर	2561578
एसपी छहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778
सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ	
इंडियन एयर लाइन्स	
छहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज	2453999
सिटी ऑफिस	2573399

रेलवे

रेलवे प्लेटफॉर्म	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	2470315

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन

बख्शी नगर	2543557
गांधी नगर	2430786
कंपनी बाग	2542582
नया प्लॉट	2573429
पंजतीर्थी	2547537
दूरसंचार विभाग	
डायरेक्टरी पुस्तकालय	197
फॉल्ट रिपेयर	198
ट्रंक बुकिंग	180
बिलिंग शिकायत	2543896
जम्मू नगर पालिका	
जं. लाइन्स	2578503
प्रशासन अधिकारी	2542192
स्वास्थ्य अधिकारी	2547440
आक सेवाएँ	
मुख्य डाकघर छहर	2543606
गाँधी नगर	2435863
अग्निशमन सेवाएँ	
नियंत्रण कक्ष	101, 132, 2476407
छहर	2544263
गाँधी नगर	2457705
नहर	2554064
गंग्याल	2480026
रखौई गैस डीलर	
चिनाब गैस	2547633
गुलमीर गैस	2430835
लैकफेड	2548297
एचपी गैस	2578456
शिवांगी गैस	2577020
तवी गैस	2548455
पावर हाउस	
गाँधी नगर	2430180
नहर रोड	2554147
जानीपुर	2533828
नाजक नगर	2430776

परेड	2542289
सतवारी कैंट	2452813
अस्पताल	
जीएमसी अस्पताल	2584290
एस.एम.जी.एस. अस्पताल	2547635
सी.डी. अस्पताल	2577064
डेंटल अस्पताल	2544670
गांधी नगर अस्पताल	2430041
सरवाल अस्पताल	2579402
जी.बी. पंत कैंट अस्पताल	2433500
आयुर्वेदिक कॉलेज	2543661
सी.आर.पी. अस्पताल	2591105
आचार्य श्री चंदर	2662536
मानसिक अस्पताल	2577444
स्वामी विवेकानंद	2547418
ब्लड बैंक	2547637
एम्बुलेंस	2584225, 2575364
एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)	2543739
नर्सिंग होम	
मदन अस्पताल	2456727
मेडिकेयर	2435070
त्रिवेणी नर्सिंग होम	2452664
सुविधा नर्सिंग होम	2555965
अल. फिरोज नर्सिंग होम	2545050
आस्था नर्सिंग होम	2576707
बी एन चैट्टीबल ट्रस्ट	2505310
चोपड़ा नर्सिंग होम	2573580
हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल	2541952
जीवन ज्योति	2576985
युद्धवीर नर्सिंग होम	2547821
मीडियाएड नर्सिंग होम	2466744
सीता नर्सिंग होम	2435007
विभूति नर्सिंग होम	2547969
रामेश्वर नर्सिंग होम	2580601
बी एन चैट्टीबल	2555631
महर्षि दयानंद	2545225

देशभक्ति का नया नाप : 56 इंच से आगे, पेट, जेब और पोस्टर



मज्कूर आलम

देश में ऐसे ऐतिहासिक क्षण बार-बार नहीं आते, जब लाल किले के प्राचीर से भाषण सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति या विकास योजनाओं पर न होकर, सीधे आपकी कमर, पेट और जेब की परिधि पर वार करे। इस वर्ष (2025) का स्वतंत्रता दिवस इसी श्रेणी में रखा जायेगा कृ प्रधानमंत्री ने मोटापे को राष्ट्रीय चिंता घोषित किया, साथ ही आर्थिक मोर्चे व राष्ट्र-छवि सुधार के नए नुस्खे भी पेश किये। अब यह देश के नागरिकों को समझना है कि पेट और पगार दोनों का आकार कंट्रोल में रखना ही असली राष्ट्र निर्माण है, क्योंकि जब पेट और जेब दोनों हल्के हों, तो मन अपने आप भारी-भरकम देशभक्ति से भर जाता है।

‘पेट और देशभक्ति कृ एक सीधा संबंध’

देशभक्ति मापने के लिए पहले इंच-टैप इन्होंने इस्तेमाल किया था। कभी 56 इंच के सीने पर जोरदार जोश उबलता था। फिर ताली-थाली पर। अब बात पेट तक आ पहुँची है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आपकी छवि सिर्फ विदेश नीति से नहीं, बल्कि पेट की गोलाई से तय होती है कृ जिस तरह जी-20 में सूट सिलवाने से पहले शरीर नापा जाता है, उसी तरह वैश्विक राजनीति में देश की छवि मापने से पहले पेट तौला जाता है।

और यहीं प्रवेश करते हैं हमारे राष्ट्रवादी चिंतक दिलीप सी मंडल कृ वे महापुरुष, जिनका कलम कभी सत्ता के खिलाफ तलवार की तरह चला करता था, पर आज सरकारी नारों के लिए मृदंग की तरह बजता है। उनका हालिया वक्तव्य कृ “इतना मत खाओ कि फट जाओ” कृ कोई सामान्य सलाह नहीं, बल्कि गहन राष्ट्रवादी उद्घोषणा है। मानो कह रहे होंकृ ‘जो थाली संभाल न पाये, वह देश क्या संभालेगा’।

‘विचारधारा और चर्बी का प्रबंधन’

याद दिला दें कृ यही देशी चिंतक 2018 में गर्व से बताते थे कि 2001 से पहले संघ मुख्यालय में तिरंगा फहराने की परंपरा नहीं थी, और यह कोर्ट के आदेश के बाद ही शुरू हुआ। तब उनकी नज़र देश के सीने की माप पर थी। आज वही निगाह देश के पेट की माप और उसके भूगोल पर है।

यह बदलाव किसी को ‘यू-टर्न’ लग सकता है, लेकिन दरअसल यह ‘विकासशील मानसिकता’ है कृ जो सही समय पर हल्की हो जाये, वही लंबे समय तक टिकती है। विचारधारा और चर्बी, दोनों का यही सिद्धांत हैकृ अवसर देखकर घटाओ, ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाओ।

कह सकते हैं, यह देशभक्ति का ‘लो-फैट’ संस्करण हैकृ कम वसा, ज्यादा स्वाद।

‘पगार पर नयी राष्ट्रीय दृष्टि’

प्रधानमंत्री जी की एक और घोषणा कृ अगर किसी परिवार से कोई सदस्य पहली बार प्राइवेट नौकरी में जायेगा, तो सरकार उसे पंद्रह हजार रुपये देगी। सुनने में यह योजना मोटापा घटाने जितनी ही आकर्षक है, लेकिन इसमें भी ‘कैलोरी चार्ट’ छिपा है कृ सरकारी नौकरी की थाली अब इतनी छोटी हो गयी है कि उसमें सबको बैठाना संभव नहीं, इसलिए कहा जा रहा है कि जाओ, कहीं और खाओ, लौटो



तो थाली में मिठाई रख देंगे।

अगर इस पर हमारे देशी चिंतक कुछ लिखते, तो शायद कहते कृ “सरकारी नौकरी छोड़ो, पंद्रह हजार लो और राष्ट्रहित में कॉरपोरेट कैटीन का पिट्ज़ा खाओ। ये भी एक तरह का उपवास है, क्योंकि तनखाह का आधा हिस्सा टैक्स में वापस राष्ट्र को जायेगा।”

यानी आपको नौकरी भी निजी करनी है, और पेट भी निजी रखना है कृ सरकार सिर्फ ताली और थाली बजाने का कॉन्ट्रैक्ट रखेगी।

टैरिफ की दीवार और राष्ट्रहित

इसी भाषण में टैरिफ वार पर भी बात आयी। घोषणा हुई कि विदेशी अनाज, दूध, मछली आयी और किसान-मछुआरे बर्बाद हो जायें — ऐसा हमारे रहने तक नहीं होगा। विदेशी माल रोकने के लिए दीवार खड़ी रहेगी।

हमारे देशी चिंतक ने इस पर तुरंत कहाकृ “भेदी हैं, तो किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं।”

अब यह बात अलग है कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले या न मिले, मछुआरों की नाव किनारे सड़ें या सागर में, लेकिन विदेशी दूध रोकने का संकल्प ही असली राष्ट्रभक्ति है, क्योंकि पेट भले खाली हो, पर वह विदेशी नहीं होना चाहिए।

‘स्वतंत्रता सेनानियों की कतार और बैकग्राउंड की राजनीति’

और इस बीच, स्वतंत्रता दिवस के हफ्ते में ही, पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुभकामना पोस्टर में गांधीजी को थोड़ा साइड में खिसका दिया और वीर साव. रकर को बीच में और उनसे ऊपर खड़ा कर दिया। यह सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन नहीं, बल्कि एनर्जी सेक्टर में नयी ऊर्जा नीति है कृ जिसमें पेट्रोल, डीज़ल और पोस्टर में पोजिशनिंग, सब रणनीतिक मानी जाती है।

हमारे देशी चिंतक को देखकर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं कृ जब वे ऐतिहासिक तथ्य सुधार में उतने ही तत्पर थे जितने स्वास्थ्य सुझावों में आज

इस स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने मोटापे को राष्ट्रीय चिंता घोषित कर पेट और पगार दोनों को नियंत्रण में रखने को असली राष्ट्रनिर्माण बताया। देशी चिंतक दिलीप सी मंडल अब पेट-नियंत्रण और विदेशी माल-प्रतिरोध को देशभक्ति मानते हैं। सरकारी नौकरी घटने पर प्राइवेट रोजगार और 15 हजार की प्रोत्साहन राशि को भी राष्ट्रहित बताया गया। महंगाई में संयम, उपवास और लो-फैट देशभक्ति का नया संस्करण उभरा हैकृजहाँ पेट, पगार, टैरिफ, पोस्टर पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया संतुलन ही असली राष्ट्रीय कर्तव्य है।

हैं। कभी वे बताते थे कि सावरकर ने छह नहीं, सिर्फ पाँच माफ़ीनामे दिये थे। तब यह संख्या की राजनी. ति थी, आज यह फोटो के कोण की। फर्क बस इतना है कि पहले इतिहास का वजन तौला जाता था, अब फोटो में पेट और बैकग्राउंड का।

‘महंगाई और संयम का अद्भुत तालमेल’

महंगाई के इस दौर में देर रात भोजन त्यागना, मीठा और तेल कम करना कृ ये सब न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, बल्कि रसोई गैस, बिजली और दाल-तेल की खपत भी घटाते हैं। यह मानना पड़ेगा कि हमारे देशी चिंतक का स्वास्थ्य अभियान, वित्त मंत्रालय की ‘कमी की नीति’ के साथ बखूबी मेल खाता है। इसीलिए वे इन चीज़ों के साथ अपने फेसबुक पोस्ट में उपवास की बातें भी करते हैं।

असल में, उपवास यहाँ धार्मिक-सांस्कृतिक क्रिया

नहीं, बल्कि एक आर्थिक रणनीति है कृ गुम खाओ, कम खाओ, बचत करो और बचाये पैसे से बिजली का बिल भरो। इससे पेट का आकार भी घटेगा और सरकारी सब्सिडी का बोझ भी। यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि देश के बजट में जो कमी है, वह आपके पेट से पूरी हो जायेगी।

वजन घटाने और विचार परिवर्तन की समानता दोनों में पहला कदम है कृ त्याग। जैसे चीनी छोड़ना कठिन होता है, वैसे ही पुराने आलोचनात्मक वक्तव्यों को छोड़ना भी। लेकिन जब दिलीप सी मंडल ने 2018 वाला वक्तव्य डिलीट कर दिया, तो देशी चिंतक ने एक विचार कम किया, जैसे शरीर से एक किलोग्राम वजन घट गया हो और जब साव. रकर की माफ़ी वाला डिलीट करेंगे, जो एक-दो दिन में कर ही देंगे, तो 1008 ग्राम वजन और कम कर लेंगे। फिर आता है प्रतिस्थापन कृ चीनी की जगह गुड़ और आलोचना की जगह प्रशंसा। शुरुआत में स्वाद अजीब लगता है, मगर कुछ दिन बाद पेट भी हल्का लगता है और सोशल मीडिया टाइमलाइन भी।

ये वही प्रक्रिया है, जिसमें मोटापा घटता भी है और सरकार का वजन आपके कंधों से उतरकर आपकी जेब में बैठ जाता है।

निष्कर्ष

देशभक्ति का यह नया पंचकोण चार्ट है कृ पेट, पगार, टैरिफ, पोस्टर पॉलिटिक्स और सोशल मीडिया संतुलन। इन पाँचों का संतुलन साधना ही असली राष्ट्रीय कर्तव्य है। जो व्यक्ति कभी विचारधारा के बोझ तले हाँफ रहा था, वही आज पेट-नियंत्रण, विदेशी माल-प्रतिरोध और बैकग्राउंड मैनेजमेंट का झंडाबरदार है।

इसलिए, देशी चिंतक की सलाह को हल्के में न लेंकृ हल्का तो आपको होना है, सलाह को नहीं, क्योंकि अब देशभक्ति का असली मापदंड बढ़ा हुआ 56 इंच सीना नहीं, बल्कि पेट, जेब और पोस्टर का नाप है। बाकी विचार-विचार सब बस बकवास है।

(नया पथ से साभार। लेखक पत्रकार और साहित्यकार हैं। संपर्क : 9717861898)

बादल फटने से प्रभावित क्षेत्रों का विधायक भारत भूषण ने लिया जायजा, जल्द राहत का विश्वास दिलाया



दिलवान क्षेत्र का दौरा करते हुए विधायक डॉक्टर भारत भूषण अन्य कार्यकर्ता

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, गुरुवार को विधायक डॉक्टर भारत भूषण ने गांव दिलवान व आसपास के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर

बादल फटने से बाढ़ प्रभावित लोगों की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द उन्हें हरसंभव मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। विधायक ने मौके पर जिला

प्रशासन से बात कर क्षेत्र से मलवा हटाने तथा पानी-बिजली आपूर्ति को सुचारू रूप से बहाल करने के निर्देश दिए। प्रशासन की कार्यवाही के बाद मलवा हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया और आवश्यक सेवाओं को

बहाल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई। इस अवसर पर मंडल प्रधान सुमन वाला, डीडीसी वाइस चेयरमैन रघुनंदन सिंह उर्फ बबलू, कैप्टन पवन, युवा नेता अमित सूदन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

नगरी में सुकरला डायग्नोस्टिक लैब का शुभारंभ

राज कुमार

नगरी। नगरी म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तरसेम पाल सैनी ने जिला अस्पताल के सामने एम/एस सुकरला डायग्नोस्टिक लैब का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने लैब के मालिक को बधाई देते हुए कहा कि यह सुविधा नगरी क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

उन्होंने बताया कि अब लोगों को जांच करवाने के लिए कठुआ नहीं जाना पड़ेगा, जिससे उनका समय और पैसा दोनों की बचत होगी। साथ ही उन्हें सस्ती व बेहतर सेवाएं यहीं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे स्थानीय लैब को सहयोग दें ताकि सभी स्वास्थ्य सुविधाएं क्षेत्र में ही सुनिश्चित की जा सकें।

उद्घाटन समारोह में मौजूद अन्य लोगों ने भी मालिक को शुभकामनाएं दीं और आशा जताई



म्यूनिसिपल कमेटी के पूर्व अध्यक्ष तरसेम और सैनी सुकरला डायग्नोस्टिक लैब का शुभारंभ करते।

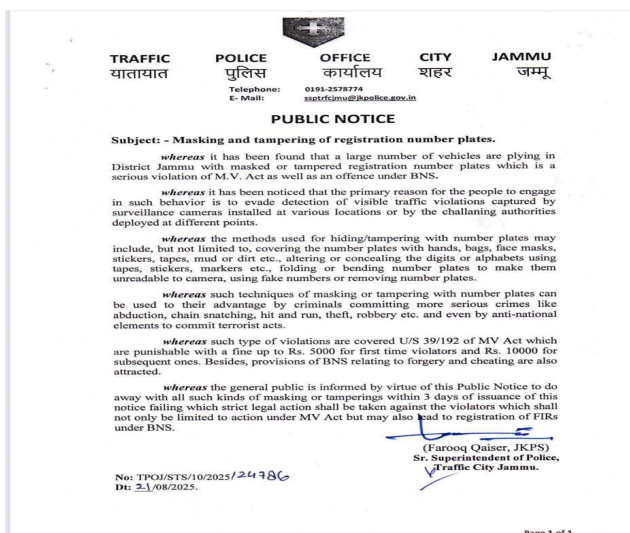
कि यहां शहर कठुआ से भी बेहतर सुविधाएं व पर डॉक्टर से परामर्श लेकर उचित इलाज करवा तेज रिपोर्ट उपलब्ध होंगी, जिससे मरीज समय सकेंगे।

जम्मू ट्रैफिक पुलिस ने नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों को दी कड़ी चेतावनी

राज कुमार

जम्मू, गुरुवार को ट्रैफिक पुलिस सिटी जम्मू ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर उन वाहन चालकों को सख्त चेतावनी दी है जो अपनी गाड़ियों की पंजीकरण नंबर प्लेट को ढककर या उसमें छेड़छाड़ कर सड़क पर दौड़ा रहे हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह मोटर व्हीकल एक्ट (डट [बज] का गंभीर उल्लंघन है और ठीक के तहत भी दंडनीय अपराध है।

पुलिस ने बताया कि कई वाहन चालक चालान व सीसीटीवी कैमरों से बचने के लिए नंबर प्लेट को हाथ, बैग, फेस मास्क, स्टिकर, टेप, मिट्टी आदि से ढक देते हैं या फिर अंकों व अक्षरों को बदल देते हैं। कई लोग नंबर प्लेट को मोड़कर या



झुकाकर कैमरे में अपठनीय बना देते हैं, नकली नंबर प्लेट लगाते हैं या उसे हटा भी देते हैं।

ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इस तरह की हरकतों केवल नियम उल्लंघन नहीं बल्कि गंभीर अपराधों

जैसे अपहरण, चोरी, स्नैचिंग, हिट एंड रन, चोरी, डकैती और आतंकी गतिविधियों में भी इस्तेमाल हो सकती हैं।

नोटिस में चेतावनी दी गई है कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 39/192 के तहत ऐसे मामलों में पहली बार 5000 रुपये और दूसरी बार 10000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, ठीक की जालसाजी व धोखाधड़ी संबंधी धाराएं भी लागू होंगी और थूट भी दर्ज की जा सकती है।

ट्रैफिक पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि इस नोटिस की तिथि से तीन दिनों के भीतर सभी प्रकार की नंबर प्लेट छेड़छाड़ या ढकने की प्रवृत्ति को तुरंत बंद करें, अन्यथा सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी

दिल्ली: सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के बाद हटाए गए पुलिस कमिश्नर, आईपीएस सतीश गोलचा होंगे नए सीपी

एजेंसी

दिल्ली पुलिस को अपना फुल टाइम पुलिस कमिश्नर मिल गया है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अफसर सतीश गोलचा को आज गुरुवार को नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। इससे पहले 'ठंडा' पदवी को पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, लेकिन वह महज 20 दिन तक ही कमिश्नर के पद पर रह सके थे। उन्हें बड रेखा गुप्ता पर हुए हमले के 30 घंटे के अंदर हटा दिया गया। आईपीएस सतीश गोलचा, जो वर्तमान में तिहाड़ जेल के महानिदेशक हैं, उन्होंने पिछले साल 1 मई, 2024 को यह पदभार ग्रहण किया था, को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेश तक दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्त किया गया है। वह 1992 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर हैं।

31 जुलाई को कमिश्नर बनाए गए थे एसबीके सिंह गृह मंत्रालय की ओर से आज जारी एक आदेश के अनुसार, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली पुलिस का 26वां कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के आईपीएस गोलचा ने एसबीके सिंह का स्थान लिया है, जिन्होंने 31 जुलाई को अपने पूर्ववर्ती संजय अरोड़ा के रिटायर होने के बाद कमिश्नर का अतिरिक्त कार्यभार संभाला था। इससे पहले गोलचा ने दिल्ली पुलिस में स्पेशल पुलिस कमिश्नर (लॉ एंड ऑर्डर), स्पेशल कमिश्नर (इंटेलीजेंस) और अरुणाचल प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने दिल्ली पुलिस में डीसीपी और संयुक्त सीपी के रूप में भी कार्य किया है।

एसबीके सिंह ने ली थी संजय अरोड़ा की जगह इससे पहले पिछले 31 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एसबीके सिंह को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया था। एसबीके सिंह 1988 बैच के अधिकारी हैं और उन्हें 1 अगस्त से दिल्ली पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। एसबीके सिंह को संजय अरोड़ा की जगह दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाया गया जो आज 31 जुलाई को रिटायर हो गए थे। एसबीके सिंह पुलिस कमिश्नर का अतिरिक्त प्रभार संभालने के दौरान दिल्ली में होमगार्ड्स के डायरेक्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे।

“सबका जम्मू कश्मीर” हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र

के लिए जम्मू कश्मीर के सभी जिला के लिए पत्रकारों की आवश्यकता है इच्छुक पत्रकार संपर्क करें

योग्यता:

- पत्रकारिता में अनुभव
- उत्कृष्ट लेखन और संवाद कौशल
- सोशल मीडिया धारण में काम करने का अनुभव

अपना बायोडाटा ई.मेल करें
sabbajammukashmir@gmail.com

संपर्क नंबर :
6005134383

महनपुर कॉलेज में राष्ट्रीय प्रतीक के सम्मानजनक उपयोग पर जागरूकता कार्यक्रम, छात्रों को दिए अहम संदेश



राज कुमार

महनपुर : सरकारी डिग्री कॉलेज महनपुर में शुक्रवार को राष्ट्रीय प्रतीक के कानूनी और सम्मानजनक उपयोग पर

जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्राचार्य डॉ. संगीता सूदन के अध्यक्षता में संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ. मोहनदेवर नाथ शर्मा ने किया। डॉ. शर्मा ने छात्रों को संबोधित

करते हुए कहा कि राष्ट्रीय प्रतीक देश की सत्ता, संप्रभुता और एकता का प्रतीक है। इसका गलत उपयोग नहीं होना चाहिए, जैसे इसे वाहना, कोपियों या अनधिकृत स्थानों पर चिपकाना पूरी तरह से प्रतिबंधित

है। उन्होंने छात्रों से अपील की कि वे इसके सम्मानजनक उपयोग के लिए खुद भी जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय प्रतीक केवल पहचान ही नहीं, बल्कि देश की संस्कृति, विरासत और मूल्यों का दर्पण है। अशोक स्तंभ से लिए गए इस प्रतीक में भारतीय संस्कृति की गहराई और नैतिकता झलकती है। इस मौके पर छात्रों को प्रतीक के ऐतिहासिक महत्व पर आधारित एक वीडियो भी दिखाया गया।

कार्यक्रम में छात्रों व फैकल्टी सदस्यों ने भाग लिया। इस अवसर पर डॉ. सपना देवी, डॉ. रुपाली जसरोटिया प्रो. बिंती शर्मा, लाइब्रेरियन निशा कुमारी, रमेश, किशोरी लाल, मैंगो राम, कुलदीप, अनुराधा और सुरिंदर कुमार सहित अन्य उपस्थित रहे। पूरा कार्यक्रम डॉ. मो. हनिंदर नाथ शर्मा ने ही संचालित किया।

सांझी मोड़ में डॉ. आंबेडकर जीवन संघर्ष पर प्रतियोगिता

सबका जम्मू कश्मीर

मढ़ीन/सांझी मोड़ रु तहसील मढ़ीन के साथ लगते सांझी मोड़ (पावर हाउस के पास) निजी स्कूल में आगामी रविवार 24 अगस्त 2025 को परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा सुबह 10 बजे से 11 बजे तक संपन्न होगी। इस अवसर पर प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन द्वारा 16वीं प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसका विषय "डॉ. भीमराव आंबेडकर का जीवन संघर्ष" रखा गया है। प्रतियोगिता का उद्देश्य विद्यार्थियों



में डॉ. आंबेडकर के विचारों और उनके संघर्षपूर्ण जीवन से प्रेरणा लेना है।

कठुआ आपदा पीड़ितों के लिए डॉ. जितेंद्र सिंह का बड़ा ऐलान, 25 करोड़ अस्थायी और 150 करोड़ स्थायी पुनर्वास पर खर्च होंगे



सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : बादल फटने और बाढ़ से तबाह हुए कठुआ जिले के लोग। को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों के अस्थायी पुनर्वास के लिए 25 करोड़ रुपये और स्थायी पुनर्वास के लिए 150 करोड़ रुपये का

अनुमान तैयार किया गया है। डॉ. सिंह ने यह भी भरोसा दिलाया कि जरूरत पड़ी तो प्रभावितों की मदद के लिए एमपीलैड फंड का भी इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर हाल में आपदा पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और उन्हें जल्द से जल्द राहत और सहायता पहुंचाई जाएगी।

गांव खोख्याल में पानी का जल स्तर बढ़ने से भारी तबाही, घरों में घुसा पानी



गांव खोख्याल में जल सत्र बढ़ाने से आरा मिल को हुए नुकसान की तस्वीर

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, 19 अगस्त: बीते सप्ताह कंडी क्षेत्र में बादल फटने से जहां जान-माल का नुकसान हुआ, वहीं मैदानी इलाकों में भी जल स्तर बढ़ने से लोगों को भारी तबाही का सामना करना पड़ा।

जानकारी के अनुसार, जिला मुख्यालय के साथ लगते गांव खोख्याल में जल स्तर बढ़ने से दर्जनों घरों में पानी घुस गया, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। गांव के निवासी शिवकुमार के अनुसार, उनके आरा मिल में आई बाढ़ से मोटर मशीनें डूब गईं और माल को

लेकर भी भारी हानि हुई है। इसके अलावा किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। खेतों में लगी मोटरों और कृषि उपकरण पानी में डूब गए हैं। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से गुहार लगाई है कि वे स्थिति का संज्ञान लेकर उन्हें उचित राहत और सहायता प्रदान करें।

हीरानगर पुलिस का शिकंजा, 8.45 ग्राम चिट्टा सहित तस्कर दबोचा

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ : नशे के खिलाफ कठुआ पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना हीरानगर पुलिस ने तरनाह पुल (चक्रा) इलाके में लगाए गए नाके के दौरान एक युवक को 8.45 ग्राम हेरोइन (चिट्टा) जैसी नशीली सामग्री सहित गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की।

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, थाना हीरानगर की टीम इंस्पेक्टर आशीष शर्मा की अगुवाई में तथा एसपी ऑफिस कठुआ मुकुंद टिबरेवाल आईपीएस और एसडीपीओ बॉर्डर धीरज काटोच की देखरेख में नाका छूटी पर थी।

इस दौरान संदिग्ध हालत में आ रहे एक युवक को रोककर तलाशी ली गई।

युवक की पहचान रंजा पुत्र नशार दीन



निवासी सुनखाल हाल निवासी चन्न खत्रियां, तहसील हीरानगर के रूप में हुई। तलाशी के दौरान उसके पास से 8.45 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।

पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को दबोचते हुए थाना हीरानगर में एफआईआर नंबर 120/2025

धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

बरामद नशे को जब्त कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी यह नशा कहां से लाया था और इसे किन-किन लोगों तक पहुंचाना था।

सबका जम्मू कश्मीर

नाम परिवर्तन, तहसीलदार नोटिस, शोक सदेश, गुमशुदा सूचना, बेदखली, हुडा नोटिस, वैवाहिक, सार्वजनिक सूचना इत्यादि विज्ञापन

MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

NOTICE

It is hereby informed to the general public that I, MADAN LAL S/o Sh. GOKAL CHAND R/o AMALA, Tehsil MARHEEN, District Kathua (J&K), have applied for the issuance of Birth Certificate of my son namely TRINABH KALSOTRA S/o MADAN LAL, who was born on 08-03-2020. If anybody has any objection regarding the same, he/she may file his/her objection in writing before the concerned authority within seven (7) days from the date of publication of this notice. After the stipulated period, no objection shall be entertained and the Birth Certificate shall be issued accordingly.

बजुह नदी बचाओ अभियान में तेज हुआ विरोध, नगर समिति पर खुले में कचरा फेंकने का आरोप



स्थानीय लोग नगरी म्यूनिसिपल कमेटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए

राज कुमार

नगरी। कस्बा नगरी में चल रहा "बजुह नदी बचाओ अभियान" लगातार जोर पकड़ रहा है। स्थानीय लोगों की आवाज को देखते हुए अब यह आंदोलन नौवें सप्ताह में प्रवेश कर चुका है।

मंगलवार को एक बार फिर नगर समिति के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया।

जानकारी के अनुसार नगर समिति का वाहन वार्ड नंबर 2 में कचरा फेंकने पहुंचा तो स्थानीय निवासियों ने विरोध करते हुए कर्मचारियों को वापस भेज दिया। लोगों का आरोप है कि लंबे

समय से समिति गंदगी का ढेर नदी किनारे जमा कर रही है, जिससे हाल ही में आई बाढ़ में यह गंदगी घरों तक पहुंच गई थी।

गौरतलब है कि जिला आयुक्त के निर्देश पर जब नगर समिति से इस मामले में जवाब मांगा गया था, तो अधिकारियों ने कहा था कि कचरा नगर समिति और ग्रामीण विकास विभाग का है जिसे डल्ट सेंटर की अनुपलब्धता के चलते डंप किया गया था। उनका यह भी कहना था कि अब डल्ट सेंटर स्थापित हो चुका है और खुले में कचरा फेंकना बंद कर दिया गया है। साथ ही आश्वासन दिया गया था कि लीगेसी वेस्ट (पुराना कचरा) जल्द हटाया जाएगा।

हालांकि ढाई हफ्ते से अधिक समय बीतने के बावजूद न तो कचरा हटाया गया और न ही खुले में कचरा फेंकना बंद हुआ है। इसी बीच स्थानीय तहसीलदार नगरी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द राहत प्रदान की जाएगी और जहां पर कचरे का ढेर है उसे गड्ढों में दबाने की कार्यवाही की जाएगी।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

छोटा विज्ञापन बड़ा फायदा क्लासीफाईड

आवश्यकता प्रॉपर्टी लोन व्यापार ज्योतिष

बुकिंग के लिए संपर्क करें

MOB:- +91 60051-34383, +91 87170 07205

K2 LADIES GYM & K2 LIBRARY

GET IN SHAPE START TODAY

Workout join our gym

CONTACT NO.9541518471

AIRWAN ROAD NAGRI PAROLE KATHUA

JMB UPVC & ALUMINIUM INDUSTRY
AUTHORISED BY PROMINANCE UPVC WINDOW SYTSEM

A WORK OF ART

A FEAT OF ENGINEERING

PROFILE 20 YEARS WARRANTY
ACCESSORIES 10 YEARS WARRANTY

JMB UPVC & ALUMINIUM INDUSTRY
AUTHORISED BY PROMINANCE UPVC WINDOW SYTSEM

Address: Sherpur, Kathua (J&K) | M.: 9086038088, 9419162407
Email: jmbupvc@gmail.com